

मिनी-मैक्स सीरीज

सबका साथ सबका विकास

नरेंद्र मोदी



प्रभात

सबका साथ सबका विकास

नरेंद्र मोदी



प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

ISO 9001:2008 प्रकाशक

प्रशासन पर पकड़

नरेंद्र मोदी हमेशा से पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। वे सौंपे गए काम को पूरी निष्ठा और लगन से करते रहे हैं और अपना कर्तव्य निभाते रहे हैं।

राज्य में पहले जनता हताश-निराश थी और कार्यकर्ता हतोत्साहित, दूसरी तरफ गुजरात भूकंप जैसी प्राकृतिक कुदरती आपदा से जूझ रहा था। हालात इतने खराब थे कि पार्टी राज्य में उप-चुनाव तक नहीं जीत सकी थी। साबरमती विधानसभा और साबरकांठा लोकसभा उप-चुनाव समेत स्थानीय स्वशासन, तालुका और नगरपालिका चुनावों में भी कांग्रेस के हाथों भाजपा की हार से पार्टी को गहरा झटका लगा। ऐसे हताशा भरे माहौल में नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद का पदभार मिला। पद सँभालते ही उन्होंने सूत्र दिया—‘आपणु गुजरात—आगवु गुजरात’ (अपना गुजरात—अनोखा गुजरात)।

और 7 अक्टूबर, 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बाद में अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने गए थे। उन्होंने आशीर्वाद के साथ एक ही वाक्य बोला था : ‘बेटा, कोई घूस आपे तो ले तो नहीं...’ (बेटा अगर कोई घूस दे तो भी कभी मत लेना)। नरेंद्र मोदी को परिश्रम और प्रामाणिकता के संस्कार बचपन से ही माता-पिता से मिले थे, जिसका मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पूरे समर्पण भाव से पालन किया। उनका लक्ष्य था सत्ता यानी समाज सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा यह प्रथम दिन से ही दिखा।

शहर गांधीनगर। सन् 2001, धनतेरस का दिन!

पदभार ग्रहण करने के बाद वे अधिकृत रूप से मुख्यमंत्री निवास में रहने जानेवाले थे। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त था—धनतेरस का पवित्र दिन।

सब सोच रहे थे कुंभ (मंगल कलश) कौन रखेगा? संघ परिवार की कोई बहन या उनके परिवार की बहन या भाभी रखेगी? मगर ऐसा नहीं हुआ। धनतेरस के पवित्र दिन अधिकृत मुख्यमंत्री निवास पर रविना नरेशकुमार जादव नामक एक दलित बाला के हाथों कलश रखा गया। उसके पश्चात् ही नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश किया। रविना के पिता नरेश जादव दलित जाति के चतुर्थ वर्ग के सरकारी कर्मचारी थे।

मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी को शासन का कोई अनुभव नहीं था। पहले किसी सरकारी पद पर उन्होंने काम भी नहीं किया था। अब उनके पास एक ही रास्ता था—मेहनत और कठोर परिश्रम। शुरू में विभाग सह मीटिंग की शृंखला शुरू हुई। रोज रात को 11 बज जाते। उन्होंने एक ही काम किया—अधिकारियों की सुनी और काम समझना शुरू किया। मंत्रिमंडल और सीनियर अधिकारियों की टीम के साथ विशेषज्ञों से ट्रेनिंग की। विशेष विषयों पर समझ विकसित की।

धीरे-धीरे सरकारी कामकाज और उस तंत्र की काम करने की शैली को गतिशील करने में माहिर होते गए। कामकाज की असल समझ तो उनके पास थी। संगठन का अच्छा अनुभव भी था। एक-एक करके प्रत्येक क्षेत्र को नए नजरिए से देखने लगे। वर्ष 2003 में एक छोटा सा सुझाव रखा—कृषि फीडर तथा गृहकार्य उद्योग में फीडर अलग कर दें तो...? अधिकारियों के साथ खूब विचार-विमर्श हुआ, हाँ न हुई। फाइल ऊपर-नीचे होती रही। अपने सुझाव पर उनका दृढ़ मानना था कि यह संभव है पर तकनीकी दृष्टि से करने को कोई भी तैयार नहीं था। आखिर रास्ता निकला। अभूतपूर्व ‘ज्योतिग्राम योजना’ बनी।

गाँव में 28 घंटे बिजली प्राप्ति में गुजरात प्रथम राज्य बना। ज्योतिग्राम ने अभूतपूर्व विकास की नींव रखी। ग्राम जीवन स्तर ऊपर उठता गया। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को सुविधा उपलब्ध हुई, घरेलू उद्योग में तेजी आई।

यह तो बस शुरुआत थी। स्कूल को बिजली मिली तो स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाने लगा। पंचायत की कचहरी में बिजली आई तो ई-गवर्नेंस की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद प्रत्येक गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। जिससे ई-ग्राम विश्वग्राम प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। आज ऐसी स्थिति है कि गांधीनगर में बैठे-बैठे ही नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात के गाँव-गाँव में किसानों के साथ, सरपंच से लेकर कलेक्टर तक और विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा गांधीनगर में बायोटेक स्टूडियो से दूरदराज के गाँवों के विद्यार्थियों को दुर्लभ ज्ञान दिया जाता है। अधिकारियों को इस बात से बहुत ही खुशी है कि साहब, ज्योतिग्राम के लिए अडिग नहीं रहे होते तो यह सब कभी संभव नहीं होता।

नरेंद्र मोदी को जब पता चला कि शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषतः कन्या शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात पिछड़ा राज्य है, तो उन्हें भारी सदमा पहुँचा। अपनी कार्यकुशलता का उपयोग कर उन्होंने बरसों पुरानी, ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करने में किया। समग्र मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अधिकारियों को मिशन मोड़ पर केंद्रित किया। जून के महीने में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षा महोत्सव 2003 में शुरू हुआ, कवायद ने वार्षिक रूप धारण किया। आज शत-प्रतिशत रोजगारी का लक्ष्य गुजरात ने हासिल कर लिया है। प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट दृष्टिकोण से कामकाज करने की नरेंद्र मोदी की कुशलता के कारण गुजरात के अधिकारियों को देश भर में गौरव मिला है। अन्य प्रांतों में और अधिकारियों के बीच और अच्छा काम करने की जैसे स्पर्धा शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी की शासन के सफलता का यह फॉर्मूला कहेँ या रहस्य यही है—नया दृष्टिकोण और कठोर परिश्रम।

नवंबर 2001 में सभी जिला कलेक्टरों की एक मीटिंग थी। वैसे देखें तो यह घटना बहुत ही सामान्य है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान जो

हुआ, वह सभी सरकारी अफसरों के लिए बहुत ही असामान्य घटना था—

मीटिंग में सभी सरकारी अधिकारी अपनी तैयारी और मानसिकता के साथ उपस्थित थे। मीटिंग सुबह दस बजे शुरू होनी थी। सभी अफसर और मंत्रिगण के साथ मुख्यमंत्री भी निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित हो गए।

दीप प्रज्वलन के बाद अपनी बात कहते हुए नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि 'गुजरात की जनता की सेवा करने का हमें अवसर मिला है तो हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे।' उनकी वाणी में क्या जादू है किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। उपस्थित सभी अफसरों को लगा कि दीप प्रज्वलन करके मुख्यमंत्री चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कलेक्टरों की मीटिंग में सामान्यतः रेवेन्यू तथा सरकारी योजनाओं के विषय में चर्चा होती है। क्रमशः प्रत्येक विभाग की बारी आती है। विभाग के सचिव एवं मंत्री सभामंच पर उपस्थित रहते हैं और अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सभामंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। कुछ अफसर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी भी हिस्सा लेनेवाले हैं। सभी अधिकारीगण बड़ी सतर्कता से अपने कार्यों का विवरण देने लगे। आखिर मुख्यमंत्रीजी जो मौजूद थे। उनको अपने कार्य से प्रभावित भी तो करना था। समीक्षा बैठक चली, सभी मुख्यमंत्री को एकचित्त होकर सुन रहे थे।

दोपहर को भोजन के लिए अवकाश मिला। सबने सोचा कि अब मुख्यमंत्री जरूर चले जाएंगे! पर नहीं, यहाँ तो मुख्यमंत्रीजी ने सबके साथ भोजन किया और साथ में परिचय भी करते गए। अब तो जरूर जाएंगे, लेकिन नहीं! मुख्यमंत्रीजी ने फिर सभामंच पर स्थान ग्रहण किया। फिर चर्चा चली। चाय के लिए कुछ समय का अवकाश मिला। अब तो जरूर चले जाएंगे! नहीं! वे तो बड़े ध्यान से सभी विभाग के कार्य को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। उपस्थित सभी को भी लगा कि हाँ, यह मुख्यमंत्री कुछ अलग है। कार्य को जानने-समझने की उनमें जिज्ञासा है। ये जरूर कुछ विशेष कार्य करेंगे। मीटिंग में उपस्थित अफसरों, कलेक्टरों और मंत्रिगण में अनोखे-अनूठे उत्साह का संचार हुआ। सब मुख्यमंत्री से कभी विभाग और उनके कार्य को समान रूप से महत्व मिलने पर बहुत ही भावविभोर हो उठे थे। शाम छह बजे खत्म होनेवाली मीटिंग रात नौ बजे तक चली। लेकिन उस समय भी सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सुबह दस बजे मीटिंग का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री रात नौ बजे, यानी ग्यारह घंटों तक लगातार मीटिंग में बैठे। सबको बड़े ध्यान से सुना! आनेवाले दिन कैसे होंगे, यह सबकी समझ में आने लगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी को सरकारी शासनतंत्र का कोई अनुभव नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद सफल होने का एक ही रास्ता था—कठोर परिश्रम।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शीर्षस्थ क्रांतिकारियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। सशस्त्र क्रांतिकारियों को विदेश में शिक्षा और निवास आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के उपरांत शस्त्र और साहित्य की पूर्ति करवानेवाले श्यामजी कृष्ण वर्मा के परिवार में पत्नी भानुमती के अलावा कोई नहीं था। सन् 1930 में जेनेवा में उनका देहांत हुआ। देहांत से पहले उन्होंने अपनी और पत्नी की अस्थियों को सौ वर्ष तक वहाँ की सरकार सँभालकर रख सके, ऐसी व्यवस्था की थी। श्यामजी की इच्छा थी कि देश स्वतंत्र होने के बाद उनकी अस्थियाँ स्वदेश वापस लाई जाएँ। सन् 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन क्रांतिकारियों को भुला दिया गया। मृत्यु के 73 वर्ष बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रसर होकर जेनेवा सरकार से मंत्रणा की। नरेंद्र मोदी स्वयं जेनेवा गए और 4 सितंबर, 2003 को श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियाँ स्वदेश ले आए। मुंबई हवाई अड्डे से भव्य अस्थि-कलश यात्रा निकाली गई। कच्छ के मांडवी नगर में, उनकी मातृभूमि में बड़े हर्षोल्लास से अपने सपूत का स्वागत किया गया। आज उस पुण्यभूमि पर विराट् क्रांति स्मारक खड़ा है, जहाँ देश के इस महान् सपूत की अस्थियाँ देशप्रेमियों के दर्शनार्थ रखी गई हैं।

मुंबई हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय अपने कंधे पर श्यामजी की अस्थि-कलश उठाए चल रहे नरेंद्र मोदी के मनोभावों का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। इतिहास के इतने बड़े व्यक्ति की अस्थियाँ 73 वर्षों तक शायद एक सच्चे देशभक्त के मजबूत कंधों का ही इंतजार कर रही थीं। भारतमाता के सपूत होने का श्यामजी और नरेंद्र मोदी दोनों ने फर्ज निभाया।

नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रत्येक क्रांति-स्थल पर भव्य क्रांति स्मारक खड़े किए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देनेवाले देश के वीर सपूतों से आनेवाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लेती रहें, यही नरेंद्र मोदी का शुभ आशय है।

नरेंद्र मोदी को 7 अक्टूबर, 2013 को सत्तापद सँभालते हुए 12 वर्ष पूरे हुए। 7 अक्टूबर, 2001 को उन्होंने गुजरात की जनता की सुख-समृद्धि की शपथ ली थी। लगातार 12 वर्ष तक उन्होंने पूर्ण मनोयोग से तपश्चर्या कर गुजरात की सेवा की। नरेंद्र मोदी कहते हैं— 'मैं गुजरात की भक्ति में लीन हुआ।' नरेंद्र मोदी का मंत्र है— 'गुजरात मेरी आत्मा है, भारत मेरा परमात्मा है।' नरेंद्र मोदी ने 12 वर्ष में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। गुजरात के विकास की चर्चा आज पूरे विश्व में बड़े आदर और गौरव से हो रही है। गुजरात की सिद्धि और समृद्धि की चर्चा देश और दुनिया में न सिर्फ इसलिए हो रही है कि उसने आर्थिक और कृषि क्षेत्र में विकास किया, बल्कि उसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है कि उसने सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और प्रजा के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम किया है। गुजरात की जनता आज अपने आप गौरव और आत्मविश्वास से छलकती है। यह सब कठोर परिश्रम और पारदर्शी शासन के कारण हुआ है। गुजरात 1960 में एक राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। तब से अब तक सभी मुख्यमंत्रियों से नरेंद्र मोदी का सत्ताकाल अधिक समय का है। 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी ने ऐसी योजनाएँ कार्यान्वित की, जिसका अब तक किसी ने नाम तक नहीं सुना था। नरेंद्र मोदी ने शासन में आते ही गुजरात के सर्वांगीण विकास

के लिए 'पंचामृत-ज्ञान शक्ति', 'जन शक्ति', 'जल शक्ति', 'रक्षा शक्ति' और 'ऊर्जा शक्ति' की नई विचारधारा दी, जिससे गुजरात का हर क्षेत्र में विकास हुआ।

'ज्योतिग्राम' योजना में शहर से लेकर गाँवों तक 24 घंटे बिजली मिलती है। इससे गुजरात में उद्योग बढ़े तो रोजगार के अवसर भी बढ़े। गर्भवती माता और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 'चिरंजीवी योजना' पर अमल हुआ। सर्व सम्मत ग्राम पंचायत-समरस गाँव, कोर्ट-कचहरी, पुलिस केस रहित समरस और शांति है, ऐसे गाँव को सरकार विशेष पुरस्कार देती है। ई-ग्राम-विश्व ग्राम, जहाँ सेटैलाइट तकनीक से विश्व के साथ संपर्क और कंप्यूटर नेटवर्क से गाँवों में शीघ्र सरकारी सेवा, गरीब कन्याओं को विद्यालक्ष्मी बॉण्ड और सखिमंडल से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक बचत-प्रवृत्ति में सक्रिय किया गया है। नरेंद्र मोदी ने खुद को मिले उपहारों की नीलामी करके उससे प्राप्त करोड़ों रुपए कन्या-शिक्षा हेतु अर्पित किए।

बहुत ही कड़क, कठोर शासक-प्रशासक की छवि रखते नरेंद्र मोदी का हृदय वंचितों-पीड़ितों के प्रति हमेशा संवेदना, करुणा और ममता से छलकता रहा है। नरेंद्र मोदी का भाव-विश्व का रहा है—'आत्मवत् सर्वभूतेषु' तथा 'परद्रव्येषु लोप्यवत्' हमेशा उनके तन-मन में, उनके मन-हृदय में एक ही बात घुमड़ती रहती है कि समाज के दुःख-दर्द कैसे दूर कर सकते हैं? एक कार्यकर्ता का हृदय कैसा होता है? यह नरेंद्र मोदी के हर कार्य-व्यवहार में देखने को मिलता है। वैष्णव जन का हृदय रखनेवाले नरेंद्र मोदी 'पीर-पराई' जानते हैं और यह उनका जन्मजात गुण है।

गांधीनगर सचिवालय, ब्लॉक-1 के तलघर में स्थित जनसंपर्क कार्यालय में मुख्यमंत्री कार्यालय की दस बाई दस फीट की एक छोटी सी कोठरी में पाँच-सात अधिकारी कुरसियों पर बैठे थे। एक छोटी सी टेबल पर एक लैपटॉप और सामने टीवी। स्क्रीन। टेबल के सामने की कुरसी पर मुख्यमंत्री बैठे थे। उनके सामने की कुरसियाँ आगंतुकों के लिए रखी हैं। कोठरी के बाहर कई लोग कुरसियों पर बैठे हैं, उनमें कोई युवक है तो कोई वरिष्ठ जन। कुछ पढ़े-लिखे हैं तो कुछ अशिक्षित। एकदम गरीब और दीन दिखते चेहरे ही अधिक हैं। इनमें श्यामवर्णी दुबले-पतले आदिवासी समाज के रणछोड़भाई नीचे जमीन पर ही बैठे हैं। वे पाँव से अपंग हैं, चल नहीं सकते।

यह पीड़ित आदमी 300 किलोमीटर दूर, सूरत जिले के बारडोली तहसील के बड़वाणिया गाँव से गांधीनगर तक अपने लकवाग्रस्त पैर से घिसटते-घिसटते राज्य के मुख्यमंत्री के पास न्याय माँगने आया है। इस गरीब, अपंग, लाचार, पीड़ित और वंचित वनवासी के शरीर पर फटे हुए मैले-कुचैले कपड़े, गले में लाल रंग का पुराना गमछा, अस्त-व्यस्त सफेद बाल और हाथ में पोटली है।

नरेंद्र मोदी इस व्यक्ति की ओर संवेदना भरी दृष्टि से एकटक देख रहे हैं और फिर शुरू होता है वनवासी और मुख्यमंत्री के बीच संवाद—
स्नेह से नरेंद्र मोदी ने पूछा, 'भाई, तुम इतनी दूर से किसलिए आए हो?'

वनवासी कहता है, 'साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मेरे गाँव में सब लोग कहते थे कि तू अपने मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई को मिल, वे सबका न्याय करते हैं, तुझे भी न्याय दिलाएँगे, इसलिए मैं आया हूँ। मैं पहली बार गाँव के बाहर निकला हूँ।'

'बोलो भाई, क्या बात है?' नरेंद्र मोदी ने कहा।

वनवासी—'साहब के ऑफिस से कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब को सूचना मिलते ही मेरे ही गाँव के धनसुखभाई रमणभाई हलपति को घर बनाने का काम सौंपा गया। उन्होंने काम शुरू भी किया है, परंतु रेती की जगह वह (पोटली खोलकर दिखाता है) इस माल का उपयोग करता है और सीमेंट तो एकदम कम इस्तेमाल करता है। मेरे घर के दरवाजे भी तोड़ डाले हैं और मुझ पर दबाव डालकर दरवाजे लाने के लिए कहता है। मैं दरवाजे कहाँ से लाऊँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा घर वे एकदम कच्चा बना रहे हैं। मैं कुछ भी कहता हूँ तो पटवारी मुझे धमकी देता है कि पुलिस को कहकर बहुत मार खिलाऊँगा।'

टी.वी. स्क्रीन के सामने सूरत के कलेक्टर से नरेंद्र मोदी पूछते हैं, 'यह मामला क्या है?'

(सूरत जिला कार्यालय में कलेक्टर के पास बैठा हुआ सहायक अधिकारी जवाब देता है, जिसे मुख्यमंत्री और शिकायतकर्ता सामने रखे टी.वी. स्क्रीन पर देखते और सुनते हैं।)

'सर, इनके पुत्र के नाम पर मकान था, जो हलपति गृह निर्माण बोर्ड द्वारा सन् 1996-97 में बनाया गया था। शिकायतकर्ता के पुत्र के मकान के बाजू में खुली जगह है। आपस में तकरार होने पर शिकायतकर्ता का मकान तोड़ दिया गया था, परंतु बाद में समझौता होने पर पटवारी और महिला सरपंच के पति अब इस मकान को नए सिरे से बना रहे हैं।'

'मकान बनाने का काम गुणवत्ता का नहीं है और शिकायतकर्ता दरवाजे-खिड़की की माँग करने के कारण स्वागत कक्ष में उपस्थित हुआ है।'

'हलपति गृह-निर्माण द्वारा स्थान और स्थिति का जायजा लिया गया है। शिकायतकर्ता की बातों को परखा गया है और उसके पुत्र के मकान को तोड़ डालने का दबाव डाला गया है, उनकी बात सही है।'

नरेंद्र मोदी—'पटवारी के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। क्या पटवारी का काम गरीब लोगों को परेशान करने का है? मकान बनाने के लिए जिस प्रकार का सामान (मैटेरियल) ये दिखाने लाए हैं, उससे मकान नहीं बन सकता है। अभी वे जो काम कर रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं। मकान बनाने का काम सही और अच्छा हो, ऐसी उनसे अपेक्षा है। खराब मैटेरियल उपयोग में ला रहे हैं। नमूना लेकर शिकायतकर्ता आया है। नमूना देखकर ऐसा लगता है कि गलत काम हो रहा है। आप स्वयं इसकी जाँच करें कि मकान बनाने का काम जल्दी और संतोषजनक हो।'

शिकायतकर्ता आदिवासी रणछोड़भाई नरेंद्र मोदी का आभार मानता है। ऐसे कई लोग मुख्यमंत्री के शिकायत निवारण स्वागत कार्यक्रम में हर

महीने के चौथे गुरुवार को आते हैं। यह कार्यक्रम यू.एस. से पुरस्कृत भी है।

वनवासी परिवारों के लिए बनाई गई 'वनबंधु कल्याण योजना' का लाभ अंतिम छोर के वनवासी बंधु तक हाथोंहाथ पहुँचाने हेतु मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पंचमहल जिले में प्रवास कर रहे थे। वैसे तो सरकारी काररवाई आमतौर पर होती ही रहती है। लेकिन गुजरात की छह करोड़ जनता, जिसे नरेंद्र मोदी अपना परिवार मानते हैं, उससे मिलने वे स्वयं उनके द्वार पर पहुँचे। सभामंच से नरेंद्र मोदी की नजर मंच से थोड़ी दूर पर बैठे एक वृद्ध वनवासी पर पड़ी, जो उन्हें एकटक देख रहा था। नरेंद्र मोदी को उसकी नजर में आशा की किरण दिखाई दी। उन्हें लगा वह उनसे कुछ कहना चाहता है।

कार्यक्रम पूरा होते ही मुख्यमंत्री स्वयं उस वृद्ध वनवासी के पास गए। उसका हालचाल और नाम-पता पूछने के बाद कहा, 'अब बताइए, आपको कोई तकलीफ है? हमसे कुछ मदद की आपको अपेक्षा है? क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं?'

वृद्ध वनवासी नरेंद्र मोदी की इस आत्मीयतापूर्ण वाणी अभिभूत हो गया। उनसे अपने दिल की बात कही, 'साब, हमारे गाँव में बरसों से बिजली नहीं थी। आपकी सरकार ने पूरे गाँव को बिजली से झिलमिल कर दिया। लगता है जैसे पूरे जीवन से ही अँधेरा दूर हो गया। आपने हमारे इस जन्म को सार्थक कर दिया।'

नरेंद्र मोदी को आखिर जनता क्यों इतना चाहती है? यह इस वनवासी के शब्दों से ही समझना आसान होगा।

भावनगर जिले की महुवा तहसील के खाटसुरा गाँव के झवेरभाई सवजीभाई राठौड़ की फरियाद थी कि 'खाटसुरा सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड' ने पैसों की ठगी की है। इस मामले में दोषी लोगों से रकम वापस लेकर मंडली के सदस्यों को उनके हिस्से की रकम दी जानी चाहिए।

नरेंद्र मोदी ने जब झवेरभाई की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत जिला कलेक्टर से कहा, 'मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात की है कि जिला सहकारी क्षेत्र में काम कर रही हमारी सरकारी एजेंसी ने अपने कार्य में ढील क्यों बरती? छह वर्षों तक मिलीभगत कैसे चलती रही? और अब जाकर उस व्यक्ति पर मुकदमा कायम किया है? क्या उस मंडली का वार्षिक आकलन, मूल्यांकन नहीं होता? क्या उसके हिसाब-किताब की जाँच नहीं होती? इस मुद्दे को सर्वाधिक प्राथमिकता दें और जल्द-से-जल्द दोषियों को सजा मिलनी चाहिए तथा सदस्यों को उनके हक के पैसे तुरंत मिलें। इस कार्य में अब ढील नहीं बरती जानी चाहिए। इस मुद्दे को गंभीरता से निपटाएँ।'

सरकारी तंत्र में जहाँ भी भ्रष्टाचार है, कार्य समय पर नहीं होता, फिर ठीक ढंग से नहीं होता, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कड़क शब्दों में सूचना देकर उस पर अमलीकरण करवाते हैं। समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की भी नरेंद्र मोदी से न्याय की उम्मीद होती है और उसकी अपेक्षा, उम्मीद पूरी होती है और जनता नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति श्रद्धावान बन जाती है।

प्राथमिक शाला में पढ़नेवाले लड़कों को 'विद्यादीप' और लड़कियों को 'विद्यालक्ष्मी' बॉण्ड सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इसका शुभ आशय यही है कि बच्चे बड़े होकर इस राशि का उपयोग अपनी उच्च शिक्षा में कर पाएँ। अगर विद्यार्थी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो यह राशि उसके परिवार को सहायता के रूप में मिलती है। इस बॉण्ड का प्रीमियम राज्य सरकार बीमा कंपनी को देती है।

गुजरात के अमरेली जिले के मोहनभाई छनाभाई खेतारिया की बेटी को भी इस 'विद्यालक्ष्मी' बॉण्ड का बीमा कवच मिला था। बेटी का आकस्मिक अवसान हुआ। बीमा कंपनी की ओर से चार वर्ष तक बीमे की रकम मृतक के परिवार को नहीं दी गई। मृतक के पिता ने मुख्यमंत्री से फरियाद की।

नरेंद्र मोदी ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने आदेश जारी किया कि "मृतक विद्यार्थी के परिवारजनों को अरजी देने आना पड़े, यह स्थिति दोबारा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ध्यान रखे कि कितने विद्यार्थियों की मृत्यु हुई है। कितने परिवारों को बीमा कवच की सहायता राशि पहुँचाई गई है। इन सब बातों का खयाल रखने के लिए प्रत्येक विभाग में इसकी अलग व्यवस्था की जाए, जो बीमा-योजना का नियमित रूप से निरीक्षण करे। इस आदेश का न केवल शिक्षा विभाग में अमल हो, बल्कि किसान, आँगनवाड़ी के सेवक और पुलिस सभी विभागों का सरकार से सक्रिय तालमेल होना चाहिए। इसका आदेश-पत्र तत्काल जारी किया जाए और मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाए। यदि कोई बीमा कंपनी ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो उसके विरुद्ध सरकार की ओर से अखबारों में विज्ञापन दो कि यह बीमा कंपनी समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रही है। उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हाँ, मुझे एक सप्ताह के अंदर पूरे राज्य का जिलेवार रिपोर्ट चाहिए कि कितने विद्यार्थी आकस्मिक मौत के शिकार हुए हैं और कितने परिवारों को बीमा योजना की राशि पहुँचाई गई है।"

ऐसी है नरेंद्र मोदी की जनता के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता।

नरेंद्र मोदी ने जनकल्याणकारी योजनाएँ कार्यान्वित की हैं। हर योजना में संवेदना और मानवीय स्पर्श है। शाला प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षा अभियान के समय पूरी सरकार मुख्यमंत्री से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी जून महीने की कड़ी धूप-गरमी में गाँव-गाँव जाकर बच्चों का शाला में प्रवेश करवाते हैं। ऐसा ही शाला प्रवेशोत्सव का प्रसंग गांधीनगर जिले के देहेगाम तालुका के छोटे से लिहोड़ा गाँव में पूरा गाँव एकत्र हुआ था। नरेंद्र मोदी ने देखा कि एक आशा वर्कर बहन विद्यालय में दाखिल नए बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने देखा कि बच्चे को कुछ तकलीफ है। वे पास गए और पूछा, क्या तकलीफ है? उस बच्चे को पैर में गंभीर तकलीफ थी। नरेंद्र मोदी ने वहीं जिला कलेक्टर को

सूचना दी कि इस बच्चे के उपचार का पूरा खर्च सरकार देगी। वहाँ बच्चों ने मुख्यमंत्री के स्वागत में समूह नृत्य किया। नरेंद्र मोदी अत्यंत एकाग्रता से इन बच्चों का नृत्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि नृत्य कर रहे इन बच्चों में एक छोटी सी बच्ची को आँखों में कुछ तकलीफ है।

नृत्य पूरा हुआ। नरेंद्र मोदी ने बच्ची को अपने पास बुलाया। वहाँ खड़े शिक्षक को लगा, कुछ भूल हो गई लगती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़े आत्मीय भाव से, वात्सल्य से बच्ची से पूछा, 'बेटी, आँख में कुछ तकलीफ है?' उस बच्ची का नाम था—नीलू मकवाणा। उसने नरेंद्र मोदी से कहा, 'मैं कक्षा-6 में पढ़ती हूँ, बहुत छोटी थी, तब आँख में सुई लग गई थी, तब से आँख में कम दिखाई देता है।'

नरेंद्र मोदी ने बेटी के सिर पर बड़ी आत्मीयता से हाथ रखा और कलेक्टर को सूचना दी कि इस बेटी की आँख का उपचार हम कराएँगे। पूरा खर्च सरकार देगी।

हर वर्ष की तरह रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री के निवास पर नरेंद्र मोदी को राखी बाँधने के लिए सैकड़ों बहनें आई हुई थीं। इस समय नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए ब्लैक कमांडो पंडाल के बाहर खड़े थे। नरेंद्र मोदी पंडाल में आए। राखी बाँधने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक के बाद एक बहन आकर नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बाँधने लगीं। उन्होंने देखा कि उनकी सुरक्षा में लगे इन कमांडो की कलाईयों तो खाली हैं, 'सुरक्षा में लगे हुए ब्लैक कमांडो की कलाईयों पर भी राखी बाँधनी चाहिए।' उन्होंने सभी ब्लैक कमांडो को अंदर बुला लिया और बहनों से कहा कि इन भाइयों की कलाईयों पर भी राखी बाँधो। सभी बहनें कमांडो की कलाईयों पर राखी बाँधने लगीं। अपने परिवार और बहनों से दूर रहकर कर्तव्य निभाते इन ब्लैक कमांडो के हाथ पर राखी बाँधी जा रही थी। इन कमांडो के वज्र हृदय एकदम कोमल बन गए। वे एक अनोखी संवेदना का अनुभव करने लगे। कई कमांडो की आँखों में आँसू झिलमिलाने लगे।

देश के युवाओं की जिज्ञासा है कि नरेंद्र मोदी को प्रेरणा कहाँ से मिलती है। बात 2011 की है। खेल महाकुंभ, देश का सबसे सफल क्रीड़ा महोत्सव है, उद्घाटन समारोह था। उद्घाटन समारोह में मशहूर अभिनेता अक्षय खन्ना उपस्थित थे। खेल महाकुंभ मुख्यमंत्रीजी की प्रेरणा से आयोजित था। शारीरिक रूप से विकलांग लेकिन अपनी अन्य शक्तियों के कारण विशिष्ट लोग भी विशेष रूप से मौजूद थे। जब उद्घाटन समारोह की मार्चपास्ट निकली तो पहला दल इन विशिष्ट खिलाड़ियों का था। नरेंद्रभाई उद्घाटन भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने इस मार्चपास्ट में विशिष्ट बच्चों के उत्साह की बात की। गुजरात की विशिष्ट बच्चों की टीम ने उन्हें कैसे प्रेरणा दी। एक बार एथेंस जाकर आए बच्चों की सफलता ने उनको प्रभावित किया था, लेकिन इतना बोलते-बोलते तो उनका मन भर आया। उनकी आँखों में आँसू आ गए। नरेंद्रभाई का यह उर्मिल व्यक्तित्व उनको देश के राजनीतिक नेताओं से अलग पहचान देता है।

नरेंद्र मोदी की विशेषता है, अपने निजी व्यवहार में विनम्रता और सहजता बनाए रखना। स्वतंत्र भारत में प्रशासन में उच्च अधिकारियों और राजनेताओं के बीच संवाद एवं चर्चा मैत्रीपूर्ण और चिंतनात्मक तरीके से नहीं होती है। मुख्यतः औपचारिक और कृत्रिम गंभीरता से बातचीत होती है। नरेंद्रभाई ने देखा कि बहुत पढ़े-लिखे अधिकारियों के साथ यदि मंत्रीगण संवाद करें, अनौपचारिक वातावरण में सब साथ रहें तो बड़ा चमत्कार हो सकता है। इसी भावना के साथ शुरू हुई वार्षिक चिंतन शिविर की एक अद्वितीय परंपरा। इस शिविर में मंत्रीगण और सभी आइएएस अधिकारी तीन दिन साथ रहते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर तालीम में सम्मिलित अधिकारी साथ ही रहते हैं। सब साथ में योगा-व्यायाम से लेकर रात्रि के सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रम में भी साथ रहते हैं। दिन भर विकास के अनेक विषयों में चर्चा-सभाएँ होती हैं। वरिष्ठ मंत्री या खुद मोदीजी जूनियर अफसर की विचारप्रक्रिया एवं दलीलों को ध्यान से सुनते हैं। दूसरी ओर नीति एवं क्रियान्वयन पर दूसरे मंत्रियों के साथ स्वस्थ चर्चा होती है। मोदीजी के इस विचार से प्रशासन में खुलापन तो आया, साथ ही सबसे बड़ी बात यह हुई कि चुने हुए लोकप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठा संवाद एवं संबंध स्थापित हुआ।

'कच्छ के रण' में था 2005 का चिंतन शिविर। शिविरार्थी मरुभूमि में बने टेंट सिटी में रहे। मोदी दिन भर नई-नई सेवा में जुड़े अधिकारियों के साथ एक सामान्य शिविरार्थी की तरह इस शिविर में भाग ले रहे थे। रात में भोजन के बाद सब अपने-अपने टेंट में सो रहे थे। करीब सुबह 4.30 बजे एक जूनियर अधिकारी को 'चेस्ट पेन' हुआ। साथियों ने डॉक्टर को जानकारी दी। जैसे-जैसे अन्य अधिकारियों को जानकारी मिली तो वे सब अधिकारी जशवंत गांधी के टेंट की ओर चल पड़े। सबको आश्चर्य और गौरव तब हुआ जब सभी ने देखा कि नरेंद्रभाई तो पाँच बजे से ही उस अधिकारी की सेवा में जुटे थे। स्वयं अपने परिवार के सहस्य की शुश्रूषा कर रहे हों, ऐसी भावना के साथ डॉक्टरों से वे चर्चा कर रहे थे। श्री गांधी को अमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध हार्ट-हॉस्पिटल में भरती कराया गया, तब तक वे मॉनीटरिंग करते रहे। अपने व्यवहार से साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और संकट की घड़ी में 'लीडर' का क्या दायित्व बनता है, इसका एक बड़ा उदाहरण नरेंद्रभाई ने सबके सामने रखा।

एक प्रसंग हुबली शहर (कर्नाटक) से कन्नड़ भाषा में प्रकाशित होनेवाले 'सामयुक्त' दैनिक समाचार-पत्र ने छापा था। मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई का कर्नाटक में आगमन होने को था। उस समय एक गरीब दरजी की घटना प्रकाशित कर नरेंद्र मोदी के प्रति कर्नाटक के लोगों की जिज्ञासा को संतोष प्रदान करने का प्रयास किया गया था। इस घटना के पात्र हैं—'चंद्रकांत महेरवड़े'।

उससे किसी ने कहा कि गुजरात में दर्जियों की बहुत जरूरत है। गुजरात निवासी अपने किसी संबंधी से जानकारी लेकर, चंद्रकांत महेरवड़े रोटी-रोजी की तलाश में अमदाबाद की ओर निकल पड़ा।

चंद्रकांत महेरवड़े दरजी का काम कर अपना और परिवार का पेट पालता था। नई-नई शादी हुई थी। सुखी दांपत्य जीवन बिताने का स्वप्न

देखते हुए चंद्रकांत ने अहमदाबाद में आकर मेहनत की। दरजी का काम उसे मिलने लगा। उसने मणिनगर में मकान किराए पर लिया। इसी बीच पत्नी शोभा गर्भवती हुई। उसे अहमदाबाद के मणिनगर के एल.जी. अस्पताल में भरती किया गया, जहाँ पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया।

चंद्रकांत की पत्नी पाँच दिन अस्पताल में रही, परंतु अस्पताल से छुट्टी देने के समय अस्पताल वालों ने जो बिल दिया, उतनी राशि जमा करना चंद्रकांत के सामर्थ्य के बाहर था। बिना बिल चुकाए पत्नी को घर ले जाने की अनुमति मिलने की संभावना नहीं थी। अनजाना स्थान, कोई मित्र नहीं और संबंधियों ने भी ऐसे समय में मुँह फेर लिया। एक तरफ बेटी का पिता बनने का आनंद तो दूसरी ओर बिल चुकाने की चिंता।

अस्पताल में सुरक्षा कर्मचारियों ने चंद्रकांत का उदास और चिंतायुक्त चेहरा देखा तो कारण पूछा और जानकारी ली। चंद्रकांत ने उन्हें अपनी पीड़ा और कठिनाई बतलाई।

‘देखो, मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदी इस मणिनगर से विधायक हैं। वे सभी की सहायता करते हैं। तुम गांधीनगर जाओ और अपनी कठिनाई उन्हें बताओ। तुम्हें सहायता मिल जाएगी।’ सुरक्षा दल के लोगों ने कहा।

उसी चिंता में चंद्रकांत गांधीनगर में नरेंद्र मोदी के बैंगले पर पहुँचा। वहाँ निवास स्थान पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने उससे आने का कारण पूछा और जानकारी ली। चंद्रकांत ने अस्पताल का बिल दिखाया। पुलिस कर्मचारी ने उसे वहीं प्रतीक्षा करने को कहा और अस्पताल का बिल नरेंद्र मोदी के पास भेज दिया। कुछ ही क्षणों में नरेंद्र मोदी बाहर आए। उन्होंने चंद्रकांत की बात सुनी। नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपना लेटर पैड मँगाया। उस पर थोड़ी जानकारी लिखी, हस्ताक्षर कर पत्र को एक लिफाफे में बंद कर चंद्रकांत को दिया और कहा, “अस्पताल जाकर वहाँ के अधिकारी को यह पत्र दे देना।” फिर उन्होंने धैर्य बैधाते हुए कहा, “चिंता मत करना, सब अच्छी तरह से निपट जाएगा। अपनी पत्नी को मेरी शुभकामना देना।”

चंद्रकांत ने उनका आभार माना और वहाँ से अहमदाबाद के लिए निकल पड़ा। अस्पताल में आकर अधिकारियों को पत्र दिया। उन्होंने बिल की सारी राशि माफ कर दी। चंद्रकांत अपनी पत्नी और नवजात कन्या को लेकर घर आया। वह आज भी नरेंद्र मोदी को याद करता है। टी.वी. पर और समाचार-पत्र में नरेंद्र मोदी को देखते ही अपने साथ घटी घटना को याद कर रोमांच का अनुभव करता है।

सेवा और त्वरित निर्णय नरेंद्र मोदी का जन्मजात स्वभाव है। सूरत शहर में तापी में बाढ़ के कारण पानी भरा हुआ था। सरकार को काम में लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं मोरचा सँभाल रखा था। नरेंद्र मोदी सूरत पहुँचे थे और स्वयं साफ-सफाई के कार्य की निगरानी कर रहे थे।

एक सोसाइटी के पास से वे गुजर रहे थे, तभी एक नौजवान गुस्से में अपने कुछ मित्रों के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी में बैठे यह सब देखा। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। सुरक्षाकर्मी भी सकते में थे कि मामला बिगड़ न जाए। नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरकर सीधे उस नवयुवक के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, ‘बोल बेटा, क्या तकलीफ है?’ वह नवयुवक जो विरोध में बोल रहा था, अचानक शांत हो गया। उसने कहा, ‘साब, हमारी सोसाइटी में कीचड़ भर गया है। कॉर्पोरेशन के लोगों से अनेक बार कहा, लेकिन दो दिन से कोई साफ ही नहीं कर रहा है। इसलिए नाराज हूँ।’

फिर क्या था, मुख्यमंत्रीजी ने सभी अधिकारियों को बुलवाया, वहीं खड़े रहकर बोले, ‘आज रात तक इस सोसाइटी में सफाई हो जानी चाहिए,’ और लगभग 30 मिनट तक वहाँ खड़े रहे। काम प्रारंभ होने के बाद ही वहाँ से गए।

लोग नरेंद्र मोदी के इस एक्शन से प्रसन्न थे और प्रभावित भी। नरेंद्र मोदी की सफलता का रहस्य यह भी है कि वे त्वरित क्रिया में काम करते हैं, काम पर टालमटोल या उसे दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ते।

भावनगर के अलंग में पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद अगले कार्यक्रम के लिए नरेंद्र मोदी और उनका काफिला जा रहा था। हलकी-हलकी बारिश हो रही थी। मुख्यमंत्रीजी की गाड़ी के आगे पुलिस की पायलट कार चल रही थी। अचानक पायलट कार का बैलेंस बिगड़ा और जीप (पायलट कार) पलट गई। सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। पाँच पुलिस जवानों को काफी चोटें आई थीं।

नरेंद्र मोदी बारिश में भी गाड़ी से तुरंत उतरे और भीगते हुए उन जवानों को निकालने में स्वयं मदद करने दौड़े। आसपास अन्य सुरक्षाकर्मियों ने यह देखकर फुरती से सभी को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री तब तक वहीं खड़े रहे, जब तक सभी को एंबुलेंस में हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचाया गया। वहीं से जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक, सभी को निर्देश दिया कि सभी जवानों का इलाज व्यवस्थित और समुचित देखरेख में होना चाहिए।

नरेंद्र मोदी का प्रिय भजन है— ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाणे रे...।’ नरेंद्र मोदी कहते हैं—“जनप्रतिनिधि वह है, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और बिना किसी अहंकार भाव के उनके दुःखों में उनकी सहायता करता है।”

□

विकास का भागीरथ

इतिहास गवाह है, दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व किसी प्रांत और राज्य की ख्याति को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, जबकि देश ही नहीं, समग्र विश्व, कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ विकास की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहा हो। महान् उपलब्धियों और विकास के सर्वोच्च शिखर छूने के साथ-साथ जहाँ वैश्विक स्तर पर नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हों, तब ऐसे कंटि के मुकाबले के बीच जब छोटा सा प्रांत गुजरात दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करे, तो उसका श्रेय स्वाभाविक रूप से दूरदर्शी नेतृत्व को ही जाता है। गुजरात का यह सौभाग्य है, जिसे केवल दूरदृष्टा व्यक्तित्व ही नहीं, अपितु कर्मठ, ईमानदार और समर्पित मार्गदर्शक मिला है।

अक्टूबर 2001 में राज्यसत्ता की कमान सँभालने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 12 वर्ष के शासन में गुजरात ने देश ही नहीं, अपितु विश्व स्तर पर विकास के सर्वोच्च शिखर हासिल करने के साथ ही नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसीलिए, आज समग्र भारतवर्ष की जनता उनकी ओर आशा भरी निगाहों से टकटकी लगाए देख रही है कि काश! भारतवर्ष को भी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्राप्त हो। अब वे मात्र आशा या अपेक्षा ही नहीं, अपितु भारतवर्ष की जनता-जनार्दन की अंतरात्मा की आवाज बन गए हैं।

देश के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, जब देश की जनता ने किसी राष्ट्रपुरुष के नेतृत्व को दिल से इतना चाहा हो। आज पूरे देश में परिवर्तन का एक नया ही माहौल तेजी से फैल जा रहा है। यदि परिवर्तन कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि देश की गरिमा और देश के स्वाभिमान को विश्व स्तर पर स्थापित करने की क्षमता से लैस नेतृत्व को स्थापित करनेवाला परिवर्तन है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस बदले हुए वातावरण का आधार है गुजरात और गुजरात का समर्पित नेतृत्व।

मुख्यमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात का कार्यभार सँभाला, तब गुजरात जहाँ था, वहाँ से उनके 12 वर्षीय निरंतर शासन में गुजरात ने विकास के जो सर्वोच्च शिखर हासिल किए, उसके कारण देश में नई आशा का संचार हुआ। नई उम्मीद जगी है।

क्या हासिल किया गुजरात ने नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के शासन काल में?

गुजरात ने एक नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में विकास की निरंतर विकास यात्रा संपन्न की है। लेकिन इनमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो मात्र गुजरात ही नहीं, देश के अनेक राज्यों सहित पूरे देश की समस्याएँ हैं। आज देश गरीबी, बेरोजगारी, पानी, बिजली के अलावा कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। गरीबी निवारण की अनेक योजनाओं के बावजूद गरीबी घटी नहीं, उलटे गरीब बढ़ते जा रहे हैं। पानी, चाहे वह पीने का हो या सिंचाई का, देश के अधिकांश राज्यों में पानी की समस्या विकराल है। देश की राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में तो टैंकरों से पानी पहुँचाना पड़ता है, तो अन्य क्षेत्रों की तो बात ही क्या की जाए? और खेती? उसकी तो कल्पना ही दर्दनाक है। भले कृषि उत्पादन बढ़ रहा हो, परंतु कृषि अर्थव्यवस्था का क्या? किसान आज किस स्थिति में है? कृषि और बिजली दोनों में गर्भ और नाल का संबंध है! परंतु यहाँ तो दोनों की स्थिति विपरीत है। कृषि के लिए पानी चाहिए और पानी के लिए बिजली, परंतु देश के किसान को न तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है और न पर्याप्त बिजली। फलस्वरूप केवल वर्षा आधारित खेती। परिणाम सबके सामने है।

देश की आर्थिक समृद्धि के साथ गरीबी निवारण और विकास दर के लिए कृषि एवं उद्योग महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं। जब विकास के दो पहिये संतुलित हों, तभी देश का अपेक्षित विकास हो सकता है। कालांतर में ऐसा विकास ही अन्य क्षेत्रों में भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे विकास के लिए चाहिए पंचशक्ति के सदुपयोग की सोच। सर्वांगीण विकास के केंद्र में विद्यमान है—

पंचशक्ति : जनशक्ति, जलशक्ति, ऊर्जाशक्ति, ज्ञानशक्ति और रक्षाशक्ति।

कोई भी नेतृत्व जब पंचशक्ति के उपयोग के साथ उसका समन्वय करने में सफल हो, तो विकास के सर्वोच्च शिखर हासिल करना सहज और स्वाभाविक है।

यही है गुजरात के निरंतर विकास का रहस्य और यही है विकास की गुरु-कुंजी। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्रभाई मोदी ने राज्य की छह करोड़ जनता की सुख-सुविधा के लिए पंचशक्ति का आह्वान किया और इस आह्वान के साथ गुजरात ने प्रगति के पंचामृत का पान किया, जिसके पान के लिए बाकी देश की जनता आज तरस रही है। आज गुजरात देश के विकास का मॉडल है।

गुजरात में 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, खास तौर पर वर्ष 2001 से 2011 तक जो विकास और प्रगति हुई, वह सभी को आश्चर्य में डाल देनेवाली है। परंतु यह गुजरात के लिए एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आगामी दिनों में भी गुजरात की विकास-यात्रा निरंतर जारी रहनेवाली है।

पिछले बारह वर्षों के शासन में गुजरात ने कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सड़क एवं भवन, बिजली, वनवासी क्षेत्र, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, वंचितों का विकास आदि क्षेत्रों में विकास की ज्योति किरण पहुँची हो। गुजरात से संबद्ध हर क्षेत्र आज उपलब्धियों से सराबोर है।

नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की कमान सँभाली, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन में जनविश्वास की पुनर्स्थापना का था। परंतु हालात ऐसे थे कि मूल्यनिष्ठ एवं कर्मठ राजनेता के रूप में नरेंद्र मोदी को गुजरात ठीक से पहचानता

तक नहीं था। इस परिस्थिति में मात्र कुशल राजनेता और संगठक ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री और सुयोग्य प्रशासक के रूप में भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना करनी थी। मोदी का राजनीतिक जीवन गुजरात के परिवेश से जुड़ा था, लिहाजा राज्य का एक वर्ग उनके नाम से परिचित था, परंतु गुजरात उनके कार्य से परिचित नहीं था। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के रूप में वे कितने सफल होंगे, इस मुद्दे पर सवाल उठने लाजिमी थे।

अपने व्यक्तित्व एवं प्रशासन में लोगों के विश्वास की स्थापना की प्रारंभिक चुनौती से शुरू कर वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गौरवपूर्ण विजय दिलाने तक की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी।

नरेंद्र मोदी ने जब अक्टूबर-2001 में सत्ता की बागडोर सँभाली, तब शासक दल या सरकार के रूप में लोगों की ओर से भाजपा में दिखाया गया विश्वास डगमगाने लगा था। पूर्ववर्ती केशूभाई पटेल सरकार की कमजोरी और प्रशासन की शिथिलता ने जनमानस में विपरीत प्रभाव पैदा किए थे। 26 जनवरी, 2001 को आए भूकंप से चारों ओर विनाश पसरा था, इस प्रतिकूल परिस्थिति में हुए दिसंबर-2002 के चुनाव में जनता भाजपा को फिर सत्ता सौंपे, ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे थे। चुनाव में भाजपा का सफाया होने के आसार थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ही गुजरात को स्वच्छ और कुशल प्रशासन दे सकती है, जनता को यह विश्वास दिलाना वास्तव में सत्ताधारी दल और सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। इसमें भी गुजरात या देश की जनता मुख्यमंत्री या प्रशासक के रूप में नरेंद्र मोदी को पहचानती ही नहीं थी। ऐसे जनमानस में इस प्रकार की अनुभूति कराकर राज्य को विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचाने की विकट चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने थी।

राज्य को विकास-पथ पर ले जाने की चुनौती छोटी-मोटी बात नहीं थी। वर्ष 1998 के बाद कांडला में आए चक्रवाती तूफान के चलते कम बारिश के कारण पैदा हुई अकाल और अर्द्धअकाल की स्थितियों ने राज्य की विकास प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया था। इतना जैसे कम था, जनवरी-2001 में आए महाविनाशकारी भूकंप ने तो जनमानस और अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। ऐसा लगता था कि राज्य दशकों तक इन संकटों से नहीं उबर पाएगा।

प्रशासन में आपदा सहने की सामर्थ्य व वर्ष-दर-वर्ष आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बीच गुजरात को पुनः विकास की पटरी पर लाने का कार्य लगभग दुश्कर लग रहा था। गुजरात के जन-जीवन तथा अर्थव्यवस्था को ठप कर देने वाली प्राकृतिक आपदाएँ इस कालखंड में ही गुजरात के भाल पर लिखी थीं। विपरीत परिस्थितियों में भी गुजरात की शासन धुरी सँभालनी हो, तो केवल आयोजन ही नहीं, बल्कि चिंताओं को चिंतन में बदलकर जनता के स्वाभिमान को पुनः ऊर्जावान बनाकर विकास प्रक्रिया में शामिल करने का नजरिया चाहिए। प्रबल नेतृत्व मिलने पर ही राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का समन्वय कर विकास-पथ पर आगे बढ़ा जा सका।

तलहटी से प्रस्थान

सत्ता की जब बागडोर सँभाली, तब नरेंद्र मोदी धरातल पर थे। भूकंप की बरबादी सह चुका ऐसा कमजोर धरातल, जिसे ढहाने के लिए जोर के धक्के की नहीं, हलकी सी जुंभिश ही काफी थी। फिर भी 26 जनवरी, 2001 को आए विनाशकारी भूकंप के मलबे से राज्य को भूकंप की दहशत से बाहर लाना उनकी प्राथमिकता थी। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद सँभाला था। भूकंप की विभीषिका के बाद प्रशासन ने प्रभावितों तक राहत पहुँचाई और उनके पुनर्वास के लिए अथक प्रयास किए। इसके बावजूद जनमानस में असंतोष था। केवल असंतोष ही नहीं, बल्कि जनमानस में राज्य सरकार व प्रशासन के प्रति नाराजगी और धिक्कार की भावना भी पनप रही थी। भूकंप ने जमीन व मकान ही नहीं, अपितु जनमानस में भी दरारें पैदा कर दी थीं। इस प्रकार नागरिकों में असंतोष के बीच भूकंप पीड़ित गुजरात के नव सृजन का ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा हो रहे कार्यों के बारे में सही संदेश प्रचार-प्रसार माध्यमों की मदद से लोगों तक पहुँचाकर उनके मानस में पड़ी दरारों को भरने की भी जिम्मेदारी मोदी के सिर थी। जनता की नाराजगी के माहौल में राज्य को भूकंप के साए से बाहर लाने के लिए मुख्यमंत्री मोदी कर्मयोगी की तरह संघर्ष करने लगे। फल को लेकर कोई निश्चितता नहीं थी। समग्र प्रशासन की शक्ति को मोदी ने काम में लगाया। इस कार्रवाई के दौरान ही मुख्यमंत्री मोदी के मानस-पटल पर कर्मयोगी का विचार कौंधा।

लोगों की नाराजगी और धिक्कार की भावना का सामना कर रहे शिथिल प्रशासन की समस्त ऊर्जा सतेज करने के उद्देश्य से प्रशासन को कर्मयोगी के रंग में रँगने के लिए शुरू किए गए प्रयासों के बीच इसी प्रारंभिक प्रक्रिया में पड़े थे।

यह सही है कि नागरिक-असंतोष की प्रारंभिक चुनौती से निपटने के लिए शुरू में उन्होंने प्रशासन से सख्ती से काम लिया, परंतु इस प्रक्रिया के दौरान ही जन-भावना की तरंगों को पढ़ने के साथ उन्होंने प्रशासन में पड़ी अथाह क्षमता का अनुभव किया, परंतु इन अथाह शक्तियों को बाहर कैसे लाया जाए? इस मुद्दे पर हुए मनोमंथन से कर्मचारियों को कर्मयोगी का प्रशिक्षण देने का विचार जागा।

साबरमती तृप्त हुई नर्मदा से

भूकंप और दलगत दरारें जोड़ते-जोड़ते नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी प्रतिभा उभारनी शुरू की। प्रयास के अनुरूप संयोग भी पैदा हुआ। समग्र गुजरात चकोर दृष्टि से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उस सरदार सरोवर योजना की मदद से अहमदाबाद की जनता को हमेशा याद रहे, ऐसे काम का मोदी ने श्रीगणेश किया। अवसर था अहमदाबाद में सूखी-सपाट दिखने वाली साबरमती नदी को नर्मदा मैया के जल से पुनर्जीवित करने का। मुख्यमंत्री पद सँभालने के बाद मोदी ने सर्वप्रथम सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर उस विचार को लागू कर दिखाया, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इस कार्य से मात्र गुजरात ही नहीं, अपितु देश के इतिहास में नदी जोड़ने की कल्पना पहली बार

साकार की गई।

आगे बढ़ता गुजरात

उत्सव मनाने में आम गुजराती कभी पीछे नहीं रहता। कहा जा सकता है कि गुजरात के लिए तो जैसे जीवन एक उत्सव है। इस उत्सवप्रियता के परिणामस्वरूप ही देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात की सांस्कृतिक विरासत अनूठे प्रकार की रही है, लेकिन यहाँ उत्सवप्रियता की बात नहीं है। गुजरात ने इस उत्सवप्रियता के साथ ही इन उत्सवों को सहज रूप से सामाजिक जीवन में बुनकर गत वर्षों में विकास भी करके दिखाया है। निरंतर गुंजायमान, निरंतर जीवंतता और कुछ-न-कुछ नया करते रहने की गुजराती परंपरा इसकी विशिष्ट पहचान रही है। शायद यही गुजरात की अस्मिता थी और यही गुजरात की अस्मिता है। यह गुजरात का गौरव है और यही गुजरात की विशिष्ट पहचान है। गुजरात की निरंतर धड़कन, एक प्रकार की विशिष्ट वाइब्रेंसी ही गुजरात को अनूठा गुजरात बनाती है।

मोदी के चिंतन और मनन का निचोड़ था—गुजरात की विशिष्ट वाइब्रेंसी से देश और दुनिया को अनुभूति। गुजरात निरंतर धड़कता, विकसित होता और व्यापार-उद्योग क्षेत्र में अनेक प्रकार के आयोजनों के जरिए समृद्धि के पथ पर चलने वाला शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ का सामाजिक जीवन निरंतर धड़कता है, इतना ही नहीं, व्यवसाय-रोजगार के लिए देश या विदेश से जो यहाँ आता है, उसे भी निरंतर वाइब्रेंट रखने की गुजरात की जनता में क्षमता है और देश-दुनिया को इस बात का अनुभव कराना ही मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने जनवरी-2003 यानी नए मंत्रिमंडल के गठन के कुछ ही समय बाद गुजरात की जनता को एक नया नारा दिया। वह नारा था 'वाइब्रेंट गुजरात'। गुजरात को लेकर बीते वर्षों में तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने अनेक तरह के नारे दिए थे, परंतु वाइब्रेंट गुजरात जैसा नारा गुजरात की जनता के लिए एक नई बात थी। यों भी कहा जा सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात एक पहचान बन चुका था।

'वाइब्रेंट गुजरात' गुजरात की वाइब्रेंसी की अनुभूति कराने का एक दूरदर्शी आयोजन था। वाइब्रेंट गुजरात के विचार के चलते गुजरात का जनजीवन कितना जीवंत है, इसकी अनुभूति कराने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2013 की मकर संक्रांति-उत्तरायण के दौरान एक तरफ पतंग महोत्सव आयोजित किया, तो दूसरी तरफ पतंग महोत्सव के बाद गुजरात में पूँजी निवेश के लिए वाइब्रेंट गुजरात महोत्सव मनाने के लिए वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2003। दोनों ही आयोजन बहुत ही भव्य हुए।

पतंग महोत्सव की विशेषता यह थी कि इसमें उन्होंने विदेशी पतंगबाजों को बुलावा भेजा, जिससे विदेशियों को भी पता चले कि जिस गुजरात को अशांत माना जा रहा था, उस गुजरात में वास्तव में कितनी शांति है। पतंग महोत्सव के आयोजन का एक कारण यह भी था कि गुजरात के उत्सवों में मकरसंक्रांति का बहुत महत्त्व रहा है। पतंग उद्योग के साथ गुजरात और खासकर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा शहरों का मुसलिम समाज व्यावसायिक रूप से बहुत ही घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। गुजरात में यदि पतंग उद्योग का विकास हो, तो उससे मुसलिम समाज के गरीब वर्ग को आर्थिक दृष्टि से बड़ा फायदा हो। मात्र मुसलिम ही नहीं, बल्कि इस व्यवसाय से जुड़े समाज के किसी भी वर्ग की आर्थिक उन्नति का माध्यम पतंग उद्योग बन सकता है।

पतंगोत्सव के अत्यंत सफल आयोजन के चलते विश्व को गुजरात की उत्सव-प्रियता का एहसास हुआ, तो दूसरी तरफ गुजरात के पतंग उद्योग के विकास के लिए नए दरवाजे भी खुले।

वैश्विक सम्मेलन : प्रभावशाली आयोजन

पतंग महोत्सव के चलते वाइब्रेंट गुजरात के तहत 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 और 2013 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन हुआ। इस आयोजन को वर्ष-प्रतिवर्ष जैसी सफलता मिली, उससे लगता है कि गुजरात की बिगड़ी हुई छवि को गौरवपूर्ण ढंग से बाहर लाने के प्रयासों में मोदी को भारी सफलता मिली है।

आँकड़ों की दृष्टि से तमाम वैश्विक निवेशक सम्मेलन अपूर्व हैं, परंतु इनके आयोजन को प्राप्त उपलब्धि की दृष्टि से भी अद्वितीय कहा जा सकता है। इस समिट की विशेषता यह है कि देश के लगभग तमाम उद्योगपति और अर्थशास्त्री समारोह में उपस्थित थे। मात्र उपस्थित ही नहीं, बल्कि गुजरात के आर्थिक विकास में भी वे गुजरात के साथ हैं, यह बताने को वे उत्सुक थे। गुजरात के इतिहास में शायद यह कभी न हुआ हो, देश की अग्रिम पंक्ति के उद्योगपति एक समय पर, एक ही मंच पर उपस्थित थे। यह कोई छोटी घटना नहीं थी। मंच पर उपस्थित इन प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने अपने भाषणों में गुजरात के प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने जो अभिप्राय दिए, उनका भी सुर एक ही था कि उनके नेतृत्व में गुजरात सुरक्षित है। इतना ही नहीं, आगामी दिवसों में गुजरात आर्थिक विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचकर देश के तमाम राज्यों की तुलना में सबसे अग्रिम पंक्ति में होगा।

विकास की नवीनतम योजनाओं को साकार करने के लिए प्रशासनिक सुधार का दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। यही दृष्टिकोण था चिंता का नहीं, बल्कि चिंतन का! चिंतन के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण तथा दूरदृष्टि का! मुख्यमंत्री अच्छी तरह जानते थे कि इसी प्रशासन के काबिल उच्च आईएएस अधिकारियों की क्षमता लेशमात्र भी कम नहीं है। वे यह भी जानते थे कि जिनकी क्षमता इन उच्चाधिकारियों में है, उतनी ही क्षमता कुछ व्यावहारिक सीमाओं के बावजूद जिला-तहसील स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों में भी है। मुख्यमंत्री मोदी ने सोचा कि यदि कर्मचारियों के समूह को चिंतन की प्रक्रिया में स्वाभाविक तौर से ओतप्रोत किया जाए, तो अधिकारी भी कर्मचारी न रहकर कर्मयोगी बन सकता है। मोदी ने यह भी सोचा कि सामान्यतः नकारात्मक मानसिकता से काम करने का आदी यह समूह यदि समाज या किसी भी समस्या को सकारात्मक

दृष्टिकोण के साथ मूल्यांकित करने लगे, सौंपे गए काम निपटाने लगे, तो बहुत कम समय में चमत्कारिक नतीजे लाए जा सकते हैं। इसी विचार के साथ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय आईएएस अधिकारियों और जिला तथा मुख्यालयों के अधिकारियों के लिए हर वर्ष चिंतन शिविर का आयोजन शुरू किया। साथ ही राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए वर्ष 2003-2004 और 2005-2006 के दौरान गांधीनगर के अलावा जिला और तहसील स्तर पर भी अनूठा कर्मयोगी प्रशिक्षण आयोजित किया। चिंतन शिविर और कर्मयोगी प्रशिक्षण को राज्य में वी-गवर्नेंस के रूप में पहचान दी गई।

एक साथ अनेक प्रकार की योजनाओं की घोषणा, योजना का आरंभ, तेजी से उसे पूर्ण करने के लिए निरंतर निगरानी और इस प्रकार योजनाओं को अंजाम तक पहुँचाने का सुदृढ़ ढाँचा बन सका। नवरात्रि महोत्सव, पतंग महोत्सव, वाइब्रेंट गुजरात के तहत वैश्विक निवेशक सम्मेलन, कृषि महोत्सव, कन्या शिक्षा अभियान और इसके अलावा विभागों की ओर से किए जाने वाले अनेक छोटे-बड़े कार्यक्रमों से कुल मिलाकर यह स्थिति पैदा हुई कि एक काम निपटा नहीं कि दूसरा काम शुरू हो जाता। अधिकारी या कर्मचारी कभी काम से राहत का अनुभव नहीं करते। आज लगातार भागदौड़ और निरंतर व्यस्तता ही मानो प्रशासन का स्वाभाविक लक्षण बन गया है। पते की बात यह है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद अधिकारी-कर्मचारी वर्ग अब धीरे-धीरे इस प्रकार के हालात के आदी बन गए हैं। साथ ही पूर्ण किए गए कामकाज के संतोष के अनुभव के चलते भावी योजना के लिए उनमें अनूठी तरावट भी है।

चिंतन शिविरों में कार्यों पर जिस प्रकार से चर्चाएँ होती हैं और इन चर्चाओं के बाद जिस तरह फॉलोअप होता है, उसे ध्यान में लिया जाए, तो सभी को मानना पड़ेगा कि प्रशासनिक सुधार या उच्च आईएएस अधिकारियों की दृष्टि को खोलने में चिंतन शिविरों ने कुंजीरूप भूमिका निभाई है। इन चिंतन शिविरों में प्रातःकाल से ध्यान व योग के बाद अलग-अलग बैठकें शुरू होती हैं। बैठकों में संबद्ध जिला कलक्टर अपने-अपने जिले के कामकाज का प्रजेंटेशन करते हैं। प्रजेंटेशन के बाद उस पर चर्चाएँ होती हैं, सवाल किए जाते हैं। ग्राम सभाओं में हुए कामकाज की समीक्षा की जाती है। कृषि महोत्सव या कन्याशिक्षा अभियान की समीक्षा की जाती है। इन समूह चर्चाओं में कार्यपद्धति का मुद्दा हो, समस्याओं-सवालों के स्वरूप का मुद्दा हो, निराकरण कार्यपद्धति की बात हो या फिर प्रशासन की सीमाओं का प्रश्न हो, इन तमाम विषयों पर मुक्त कंठ से, नेकदिली से चर्चा होती है, जिससे एक नया माहौल पैदा होता है। इससे समस्याओं के निवारण की दिशा भी खुलती है।

सोच में बदलाव जरूरी

चिंतन शिविरों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का तत्त्वपूर्ण चिंतन तो था ही, परंतु उस चिंतन के साथ ही प्रशासन को दैनिक कामकाज के बोझ से बाहर लाने का आह्वान भी था। उनके संबोधन के अंश देखें। 'समस्या माइंड की नहीं, अपितु माइंड सेट की' है। समग्र राज्य में क्रांति की नहीं, कायाकल्प की आवश्यकता है। जो सेल निगेटिव हो चुके हैं, उन्हें रिचार्ज करना है। मेरे शासनकाल के दौरान एक भी ऐसी घटना नहीं घटी कि किसी अधिकारी को फटकार लगानी पड़ी हो। सचिव राज्य के हित में जब दलील करें, तो उस दलील में राज्य का हित ही हो। अधिकारी चिंता नहीं, चिंतन करें। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि पहुँच में हो, परंतु पकड़ में न हो। जब ऐसे लक्ष्य पकड़ में आते हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है। प्रशासन में कमजोरियाँ होंगी ही, लेकिन अच्छी बातें पकड़ेंगे, तो कमजोरियाँ अपने आप दूर होंगी। 'मुझसे नहीं हुआ, मैंने नहीं किया', जैसा अपराध भाव नहीं, बल्कि मुझे कुछ करना है का भाव होना चाहिए। निर्णय लेने में साहस दिखाइए और गलत हुआ हो, तो मेरी जानकारी में लाइए।'

'हमें वंचितों के विकास का ध्येय रखना चाहिए। लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना चाहिए। हमारे यहाँ समरस योजना को सफलता मिली, तो तीर्थग्राम को क्यों नहीं? फाइल पर डॉक्यूमेंट सीट भरना अनिवार्य किया जाना चाहिए और उसे अपेक्षित मानना चाहिए। निर्धारित समय से अधिक समय तक यदि फाइल अटकी हो, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। निजी रिपोर्ट में उसे ध्यान में लेना चाहिए। मुझे प्रशासनिक सुधार में नहीं, अपितु प्रशासनिक दक्षता में दिलचस्पी है। 'मैं यह करूँगा, अच्छी तरह करूँगा, परिणाम हासिल हो, इस प्रकार करूँगा।' इस प्रकार की सोच कर्मचारियों में जगाकर उन्हें कर्मयोगी बनाना चाहिए। मास्टर माइंड टीम बनानी है। काम से थकान न हो, काम करने का संतोष होना चाहिए। काम नहीं होने से थकान और निराशा की अनुभूति हो सकती है। सफलता और विफलता के बीच के फर्क को पहचानकर लोगों की सेवा में जीवन की आहुति देने वाले ही सच्चे लोकसेवक बन सकते हैं।

गुड गवर्नेंस

विश्व जब वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर चुका है, तब प्रशासन कैसे अछूता रह सकता है? वैश्विक परिप्रेक्ष्य बहुत तेजी से बदल रहा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या शैक्षणिक क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में देश या राज्य के लोगों या समाज को इस परिवर्तन को महसूस कर उसकी मूल धारा में शामिल होना चाहिए, लेकिन समाज या नागरिक के इस धारा से जुड़ने मात्र से काम नहीं होने वाला। इस प्रक्रिया में जब तक प्रशासन नहीं शामिल होगा, तब तक अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं किए जा सकेंगे। इसीलिए प्रशासन से जुड़े सभी लोगों को इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझकर उसके साथ कदम-से-कदम मिलाना चाहिए और इसके लिए गुड गवर्नेंस का विचार प्रवाहित किया गया। ऐसे में जब कि समाज में प्रशासन की विशेष भूमिका है, तब कर्मचारी-अधिकारी वर्ग का विशिष्ट कार्यदक्षता से लैस होना आवश्यक हो जाता है। ऐसी जागरूकता प्रत्येक कर्मचारी में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मोदी ने प्रशासन के लाखों कर्मचारियों को एक नए प्रकार का प्रशिक्षण देने का विचार रखा और वह साकार भी हुआ। इस प्रशिक्षण में राज्य के लाखों कर्मचारी शामिल हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विकास,

व्यक्ति की भूमिका, सकारात्मक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत गुणों का विकास, टीम भावना में काम करना, प्रशासनिक शक्ति तथा कार्यपद्धति का विकास था।

दो साल तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक जानने के लिए वैज्ञानिक तरीके से इस समग्र कर्मयोगी अभियान का मूल्यांकन भी किया गया। इसके निष्कर्ष दिलचस्प हैं। इस प्रशिक्षण शिविर का समग्र और समावेशी प्रभाव जानने के लिए जो सैंपल सर्वे किया गया, उसमें व्यक्ति विकास क्षेत्र में 89 फीसद तथा कर्मचारियों की कार्यशैली के विकास के मुद्दे पर 86.80 फीसद कर्मचारी वर्ग के लिए यह प्रशिक्षण बहुत ही फलदायी लगा। 89.70 फीसद कर्मचारियों ने यह जाना कि उनके व्यक्तिगत विकास में यह प्रशिक्षण बहुत ही उपयोगी रहा। इसी प्रकार प्रशासन में कामकाज में सुधार की दृष्टि से 87.90 फीसद कर्मचारियों ने राय दी कि अब तक जो कुछ काम किया है या हम जिस प्रकार काम का मूल्यांकन करते हैं, उसका विधेयात्मक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने की दृष्टि इस प्रशिक्षण के चलते हमें मिली है।

प्रशिक्षण का प्रभाव तथा सर्वे के निष्कर्षों के मुद्दों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य का एक बड़ा कर्मचारी वर्ग वैज्ञानिक पद्धति से दिए जाने वाले प्रशिक्षण की प्रक्रिया में एकसूत्रता से जुड़ा। गुजरात के प्रशासनिक इतिहास में कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य और विचारों के साथ गुजरात के लाखों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और कभी हुआ हो, तो उसके नतीजे देखने को नहीं मिले। एक तरफ राज्य के मंत्री और उच्चाधिकारी चिंतन शिविर के तार से जुड़े, तो दूसरी तरफ लाखों कर्मचारी-कर्मयोगी प्रशिक्षण शिविर के सूत्र से बँधे। इसी के परिणामस्वरूप विकास के पर्यावरण का आज राज्य में एक वातावरण सृजित हुआ है। उत्सवों की परंपरा और एक के बाद एक नई योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी के साथ किसी भी वक्त आ पड़ने वाली प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना था। इन तमाम परिस्थितियों में टिके रहकर संघर्ष करने की शक्ति और विकास प्रक्रिया बनाए रखने की अदम्य इच्छा का श्रेय इस प्रकार के अभियान को जाता है।

इस अभियान से ही बात नहीं रुकती। मात्र प्रशिक्षण लेने या चिंतन करने से ही सबकुछ दुरुस्त नहीं हो जाता। यह सब करने के बाद भी मुख्यमंत्री हों या मंत्री, उनके लिए प्रशासन को समझना जरूरी था और इस दिशा में प्रयास शुरू हुए।

प्रशासन को समझकर उसमें व्याप्त त्रुटियों के निवारण के माध्यम से गुजरात के प्रशासन के कार्याकल्प को साकार किया गया। सच कहें तो इस समग्र प्रक्रिया में लंबे धैर्य, प्रबल इच्छाशक्ति और दीर्घदृष्टि की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मोदी ने इन तीनों परिणामों का समन्वय कर गुजरात के प्रशासन के कार्याकल्प को साकार करके दिखाया है।

प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि वह समग्र विषयों को नियंत्रित तो करे ही, साथ ही नियंत्रण का एहसास भी न होने दे। प्रशासन का मजा इसी में है। इस प्रकार के प्रशासन को साकार करना हो, तो प्रशासन में संवेदनशीलता का संचार आवश्यक हो जाता है। संवेदनशीलता साकार करने के लिए प्रशासन की कार्यापलट जरूरी है। मोदी के नेतृत्व में कर्मचारियों के माइंड सेट और प्रशासनिक ढाँचा, दोनों का समन्वय कर प्रशासन का कार्याकल्प करने, प्रशासनिक नेतृत्व में कर्तव्य की भावना का आविर्भाव करने के खास प्रयास हुए। चिंतन शिविर, कर्मयोगी शिविर और प्रजेंटेशन तो इस समग्र प्रक्रिया के मात्र अलग-अलग हिस्से थे।

चिंतन शिविर और कर्मयोगी प्रशिक्षण के सहयोग से राज्य के हजारों-लाखों कर्मचारियों-अधिकारियों से संपन्न प्रशासन में एक प्रकार की गतिशीलता आई, लेकिन विशिष्ट प्रकार के इस प्रशिक्षण के कारण प्रशासन में प्राणवायु का संचार हुआ, जिससे वर्षों से निर्जीव प्रशासन की छवि में भी सुधार हुआ। प्रत्येक नागरिक को प्रशासनिक जीवंतता की अनुभूति हुई। प्रशासन में अनेक प्रकार के नित नए कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने का जोश आया। एक नए उत्साह का संचार हुआ।

एक तरफ प्रशासन को पूरे देश और दुनिया में मॉडल बनाने के प्रयास थे, तो दूसरी तरफ प्रशासन को उसकी सीमाओं से बाहर लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसीलिए प्रशासनिक सुधार के प्रयासों की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी था।

मई-2003 में इसके लिए विश्व के कुछ देशों के प्रशासनों को समझने की कोशिश की हुई। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा आदि देशों के प्रशासन को समझने के लिए प्रजेंटेशन का आयोजन किया गया। गुजरात को सार्वजनिक प्रशासन में एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए विश्व के देशों के प्रशासन को समझना आवश्यक था। इस प्रजेंटेशन में प्रशासन के दैनिक घिसे-पिटे कामकाज की मानसिकता बदलने के लिए सात सूत्री सुधार और वित्तीय प्रबंधन की पहल के पथदर्शकों की समीक्षा की गई। इसमें गुणवत्ता, उत्पादकता, नई पहल, अनुशासन, प्रतिबद्धता, जवाबदेही, जनोन्मुखता, व्यावसायिक निपुणता तथा वित्तीय प्रबंधन में कार्यवाहक एजेंसियाँ, नागरिक अधिकारिता चार्टर, गुणवत्ता प्रबंधन, वरिष्ठ सेवाएँ, नियमन और प्रबंधन, सूचना सेवा जैसी उल्लेखनीय बातों को लेकर इस सेमिनार के आयोजकों ने विस्तृत रूपरेखा समझाई। इस प्रदर्शन के साथ विभिन्न देशों से प्रशासनिक सुधार की मिली जानकारी गुजरात के लिए किस प्रकार अनुकूल हो सकती है, उस संबंध में भी इस कार्यक्रम के आयोजकों ने पूरा ब्योरा दिया।

प्रदर्शन में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए एजेंसियों की स्वायत्तता का नफा-नुकसान, भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपाय, वेतनों की स्पर्धात्मकता, चयनित नियुक्ति तथा पद्धति, कंप्यूटरीकरण, सेवा क्षेत्र की इकाइयों व गुणवत्ता, मंडलों से जुड़ी भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस तमाम विचार-विमर्श के दौरान ही सोचा गया कि सामान्य परिस्थितियों में हुए चिंतन-मनन का इस प्रक्रिया में भी उपयोग किया जाए, तो सोने में सुहागा साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इन चर्चाओं के निष्कर्ष के रूप में सामाजिक सेवाओं के ढाँचागत विकास और

विकास के कुंजी रूपी पथदर्शक, दिशासूचक के संबंध में प्रबंधन सूचना प्रणाली की व्यापकता विकसित करने के लिए संबंध सचिवों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रदर्शन का दौर

गुजरात की प्रगति के लिए दिन-रात मंथन होने लगा। हर विभाग, उसके अधिकारी और नीति-नियंता अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ अलग-अलग प्रजेंटेशन तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने भविष्य के गुजरात की तस्वीर पेश करते। इस दौर की विशेषता यह थी कि सुबह से शुरू होने वाले ये कार्यक्रम कई बार देर शाम या कुछ मामलों में रात में पूरे होते। आश्चर्य की बात यह थी कि संबंधित विभागों के सचिवों और उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री स्वयं सुबह से शाम तक प्रदर्शन में उपस्थित रहते। जब तक प्रजेंटेशन पूरा न हो, तब तक निरंतर उपस्थित रहने की यह घटना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आश्चर्यजनक ही है। मात्र उपस्थिति नहीं, अपितु घंटों संबंधित विभागों के कामकाज का गहराई से निरीक्षण करना, जो आँकड़े प्रजेंटेशन के लिए रखे जाएँ, उनके संदर्भ में वास्तविक परिस्थिति का अंदाजा लगाना, योजना के विवरणों के साथ जिन उपलब्धियों का निरूपण हुआ हो, उसकी वास्तविकता जाँचना और अंत में विचार-विमर्श के व्यापक दौर में कहाँ त्रुटि है? कहाँ नफा-नुकसान है? त्रुटियों में सुधार की कहाँ गुंजाइश है? विभाग की कार्यशैली को किस तरह उपयोग में लिया जा सकता है? इन तमाम बातों पर अधिकारी संवर्ग के साथ मुख्यमंत्री वैचारिक आदान-प्रदान भी करते। प्रशासनिक इतिहास की यह अभूतपूर्व घटना थी। शायद ही कभी किसी मुख्यमंत्री ने प्रशासन को समझने के लिए और राज्य सरकार के संबंधित विभाग के कामकाज का मूल्यांकन के लिए इतनी दिमागी कवायद की हो, ऐसा नहीं लगता।

संबंधित विभागों में घंटों चलनेवाले प्रजेंटेशन के आयोजन के समय संबंधित सचिवों के मन में भी सवाल उठने चाहिए कि आखिर यह कवायद किसलिए? घंटों तक प्रजेंटेशन करके मुख्यमंत्री आखिर चाहते क्या हैं? कहीं किसी के मन में यह खयाल आया होगा कि इतने विस्तृत प्रजेंटेशन के बाद परिणाम क्या? लेकिन आज उसके फल विभागों के कामकाज, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उसके वास्तविक परिणामों में देखने को मिल रहे हैं। यानी इस बात को मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री द्वारा तब आरंभ किया गया प्रजेंटेशन का दौर केवल समय व्यतीत करने का प्रयास नहीं था।

यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जो मुख्यमंत्री हो, उसे सब मालूम ही हो। इस अर्थ में कहें, तो संबंधित विभाग से काम लेने से पहले मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों को समझने की ईमानदारी से कोशिश की और इस कोशिश के कारण ही आज राज्य सरकार के अधिकांश विभाग एक अनुठी गतिशीलता के साथ अनेक उपलब्धियाँ हासिल कर सके हैं।

पंचामृत योजना का विचार

प्रशासनिक सुधार के तहत शुरू किए गए प्रजेंटेशन के इस दौर और कार्य-शिविरों के नतीजे वास्तव में चमत्कारिक रहे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पंचामृत का नया विचार प्रशासन को दिया। विकास क्रांति के आधार-स्तंभ के लिए पंचामृत की भावना यदि लागू की जाए, तो चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। पंचामृत यानी क्या? पंचामृत का मतलब है जनशक्ति, ज्ञानशक्ति, जलशक्ति, ऊर्जाशक्ति और रक्षाशक्ति। इन तमाम शक्तियों के आविष्कार के साथ यदि एक लक्ष्य ध्यान में रख मन से विकास प्रक्रिया का श्रीगणेश किया जाए, तो नतीजे जरूर मिलेंगे। बिलकुल सामान्य लगने वाली इस बात को मोदी ने बहुत ही सरलता और सहजता से विकास प्रक्रिया के साथ जोड़ा। सभी इस बात को मानेंगे कि यदि विकास करना हो तो, ज्ञान, ऊर्जा, जल, जन और रक्षा इन क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए मोदी ने इन पाँच शक्तियों के समन्वय से पंचामृत के विचार को प्रशासन के सामने रखा। अमृतपान से निर्जीव में भी चेतनापूर्ण जीवन का संचार होता है। इसी प्रकार इन पाँच शक्तियों के अमृत का निरूपण हो, तो विकास प्रक्रिया में भी जीवंतता आ सकती है। अत्यंत अल्पावधि में प्रशासन को उत्कृष्ट परिणाम हासिल हो सकते हैं और ये परिणाम दिखाई दिए उनके शासन काल के शुरुआती 111 दिनों में।

उद्घाटन नियत हो, तभी शिलान्यास

जब तक निश्चित दिशा-निर्देश के साथ प्रशासन को योजना के चरणबद्ध और समयबद्ध क्रियान्वयन का आयोजन कर योजना पूरा होने की निश्चित समय सीमा नहीं दी जाएगी, तब तक परिणाम की कोई गारंटी नहीं रखी जा सकती। कभी-कभी ऐसा भी होता कि मुख्यमंत्री को अच्छा लगने के लिए योजनाओं का उद्घाटन हो जाता, लेकिन बाद में जितना हुआ—उतना करके गाड़ी को जबरन धक्का लगाया जाता। ऐसे में मोदी प्रशासन के उच्चाधिकारियों को इस मानसिकता से उबारने के लिए खुलेआम कहते, ‘जो योजनाएँ पूरी नहीं होनी हैं, उनके उद्घाटन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि योजना का उद्घाटन कराना है, तो इस योजना के पूरी होने की तारीख मुझे बताइए। पहले योजना पूरी होने की तारीख, फिर उद्घाटन की तारीख।’ इतना आश्वासन माँगा जाए, तो फिर क्या होगा? आयोजन ही इस प्रकार से करना पड़े कि योजना उसकी समयसीमा में संबद्ध चरण में पूरी हो। यहाँ कहने का आशय यह नहीं है कि मुख्यमंत्री या सरकार ऐसा आश्वासन देने के बाद जल्दबाजी में योजना जैसे-तैसे पूरी कराना चाहते थे। आशय इतना ही था कि एक बार समयसीमा तय कर दी जाए। यदि उसमें मान लीजिए विलंब भी हो, तो उसे समझा और बरदाश्त भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई निश्चित समयसीमा तो होनी चाहिए न? किसी भी समय योजना शुरू हो और किसी समय पूर्ण हो, ऐसी योजनाओं का लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं है। बस यही बात प्रशासन समझ सके, तो योजनाएँ तेजी से पूर्ण हों, इस बात में

कोई संदेह नहीं है। योजना में गतिशीलता आएगी और निश्चितता भी आ सकती है।

स्पष्ट दिशा-निर्देश

दिशा-निर्देश और समयबद्ध आयोजन को सरल बनाने के लिए प्रत्येक विभाग को लक्ष्य दिया गया। संबंधित विभाग से कौन-कौन से काम शुरू किए गए हैं या आगामी दिनों में शुरू किए जाने हैं? यह तय करने की प्राथमिकता मुख्यमंत्री के पास तब थी। विभागों में घंटों चले प्रजेंटेशन और संबंधित सचिवों के लिए आयोजित कार्य शिविरों का उद्देश्य इस प्रकार की प्राथमिकता के मुताबिक तेजी से क्रियान्वयन ही था। मोदी ने प्रजेंटेशन के दौरान प्रशासन की सीमा, संबंधित विभाग के कामकाज की पृष्ठभूमि तथा उसके आधार पर उसकी कार्यक्षमता का एक आकलन निकाल लिया था। उस आकलन के आधार पर संबंधित विभाग को एक स्पष्ट दिशा-निर्देश देकर आगामी पाँच वर्षों के कार्यकाल के कामकाज का एक ब्ल्यू प्रिंट मन-ही-मन तैयार कर लिया गया था। उसी दिमागी ब्ल्यू प्रिंट के आधार पर समृद्ध गुजरात की इमारत के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। चिंतन शिविर कर्मयोगी प्रशिक्षण के कारण प्रशासन में नई उमंग और उत्साह का संचार तो हो ही चुका था। अब बात थी उस उत्साह और उमंग को क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जुटने की। जोश था और कुछ नया करके दिखाने का उत्साह भी था। प्रशासन के प्रत्येक विभाग के लिए संबंधित वर्ष के अनुसार अगले पाँच साल में क्या करना है? कौन सी योजनाएँ कब पूर्ण करनी हैं? उसका विभाग में विचार होता था। फलस्वरूप आज हर विभाग उसके कामकाज के निश्चित परिणामों का गौरवपूर्ण उल्लेख करने की स्थिति में है।

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के ध्येय और लक्ष्य के अलावा गुड गवर्नेंस को केंद्र में रखकर कार्यकुशल प्रशासन, प्रभावी प्रबंधन आदि मुद्दों को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई। विभागों को योजनाओं, उनके क्रियान्वयन का स्वरूप, ध्येय, लक्ष्य जैसी बातों पर पर्याप्त ध्यान देकर जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उसकी विभागवार जानकारी यही बताती है कि दिसंबर 2002 के चुनाव जीतने के बाद प्रशासनिक सुधार के लिए नई दृष्टि के साथ जो भी आयोजन मुख्यमंत्री ने किए, उसके नतीजे अब मिलने लगे। ये नतीजे बहुत ही उत्साहवर्धक रहे। यशस्वी सिद्धि हासिल करने का मानो जादुई चिराग मिल गया। उस समय ऐसा लगता कि ऐसी दिमागी कवायद यदि पिछले वर्षों में किसी भी स्तर पर थोड़ी-बहुत हुई होती, तो गुजरात का भविष्य आज से ज्यादा उज्ज्वल होता?

सिलसिला समीक्षा का दौर

विकास रेखा को अंकित करने के लिए जिन विभागों को लक्ष्य सौंपे गए, उनमें सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार, नर्मदा व जल संसाधन जलापूर्ति, कल्पसर, वन एवं पर्यावरण, राजस्व, वैधानिक और संसदीय मामलों का विभाग, कृषि एवं सहकारिता, खेलकूद व युवा, सांस्कृतिक मामलों का विभाग, विधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास एवं शहरी ग्रामीण निर्माण, वित्त, सूचना एवं प्रसारण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सड़क एवं भवन, ऊर्जा एवं पेट्रो रसायन, बंदरगाह व मत्स्योद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, उद्योग एवं खान, पंचायत-ग्रामीण गृह-निर्माण एवं ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग शामिल थे। प्रशासन विभाग में प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर कर्मचारियों को विश्वसनीय प्रशिक्षण देने का आयोजन किया गया।

हजारों कर्मचारियों को सरदार पटेल प्रशासनिक प्रशिक्षण व अध्ययन केंद्र स्पीपा के तहत ईडीपी प्रशिक्षण को लक्ष्य बनाया गया। सर्वाभिप्राय अभियान के तहत आनुषंगिक नीतियों को लागू करने की योजना बनाई गई। पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण विभागों के खर्च तथा भौतिक उपलब्धि की प्रगति के विनिमय के कामकाज के साथ जुड़े सचिवों की हर तीन माह में समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया।

जहाँ तक सामान्य जनता का संबंध है, तो राजस्व एवं पंचायत विभाग के कामकाज के लिए यदि लक्ष्य दिए जाएँ और समयसीमा में लक्ष्य पूर्ण किए जाएँ, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आम आदमी को मिल सकते हैं। आज से तीन साल पहले हर ग्रामीण को राजस्व विभाग के अधीनस्थ जिला तहसील स्तर के कामकाज में लचरपन का अनुभव होता था। एक सामान्य दस्तावेज या फिर छोटी-छोटी बातों के लिए कई दिन कचहरी के धक्के खाने पड़ते थे। आज नहीं, कल। कल जाएँ, तो अभी काम बाकी है, अगले सप्ताह आना। ऐसे जवाब सुनकर, जेब के पच्चीस-पचास रुपये खर्च करके तहसील या जिला मुख्यालय पहुँचे ग्रामीण को निराश होकर लौट जाना पड़ता था। फलतः प्रशासन को लेकर जनमानस में बहुत खराब छवि थी। राजस्व और पंचायत विभाग के कामकाज को परिणामदायी बनाया जाए, तो प्रशासन की समग्र छवि तेजी से सुधारी जा सकती है। इस बात का अहसास होते ही मुख्यमंत्री ने इन दोनों विभागों के कामकाज में सुधार पर विशेष जोर दिया।

कृषि में समृद्धि

गुजरात के सर्वांगीण विकास का आधार कृषि विभाग के कामकाज और परिणामों पर आधारित होता है। यदि कृषि उत्पादन बढ़ाने में सफलता मिले, तो राज्य की आर्थिक समृद्धि अवश्य बढ़ेगी। गत वर्षों में बार-बार वर्षा की अनियमितता, लगातार अकाल के पैदा होते हालात और अकाल के परिणामस्वरूप चौपट हो चुकी खेती के चलते गाँव भी टूटने लगे थे। इस परिस्थिति का निवारण करने तथा कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए योजनाबद्ध प्रयास जरूरी थे। 2004-05 से प्रयास हुए भी। ध्येय रखा गया कि गुजरात एग्रो विजन से टिकाऊ खेती के विकास का ध्यान रखते हुए ग्रामीण जनता को रोजगार के विशाल अवसर देकर उसकी आय बढ़ाकर किसानों का जीवन स्तर सुधारना। नए वैश्विक कृषि माहौल में टिकाऊ कृषि उत्पादकता में वृद्धि और अधिक मूल्योपार्जन से उसकी माँग के आधार पर कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास को गति दी जा सकती है। इस ध्येय को साकार करने के लिए कुछ उद्देश्य भी तय किए गए।

जो उद्देश्य तय किए गए, उनमें शत-प्रतिशत वार्षिक दर हासिल करने के लिए कृषि उत्पादन मूल्यवर्धित कर विकास को गति देना, किसानों को अत्याधुनिक तकनीक और अच्छी-से-अच्छी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जानकारी देना, कृषि में आवश्यक तमाम कृषि सामग्री जैसे आनुवंशिक संशोधित संवर्धक और असंवर्धक बीज, रासायनिक व जैविक खाद तथा कीटनाशक राज्य में उपलब्ध कराना। जैविक सेंद्रिय व असेंद्रिय कृषि रसायनों में समाविष्ट पोषक तत्वों का सही प्रमाण में उपयोग करना तथा समन्वित कीट व्यवस्था कार्यक्रमों से किसानों को अवगत कराना, मुख्य कृषि उत्पादन बाजार समितियों की ढाँचागत सुविधाएँ मजबूत करना, बागवानी क्षेत्र में रोगमुक्त फलीय पौधे उत्पादित करना, डेयरी क्षेत्र में अधिक उत्पादन देने वाली नस्लों को सहकारिता के माहौल में अपनाना आदि उद्देश्य थे।

जनता की सुख-सुविधा के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए भी उद्देश्य तय किए गए। इसमें बाल मृत्यु दर घटाना, माता के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा लाना, जनसंख्या नियमन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, जिला कार्यालयों के साथ जी-स्वैन कनेक्टिविटी, आयुर्वेदिक फार्मसी का आधुनिकीकरण, आयुर्वेदिक वनस्पति उद्यान का विकास करना, आयुर्वेदिक अस्पतालों का विकास, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक पद्धति के नए दवाखाने शुरू करना आदि शामिल थे।

गुजरात के 50 वर्षों के इतिहास में पीने और सिंचाई के पानी की समस्या हरदम पीड़ा देती रही है। गुजरात की जनता औसत 10 में से सात वर्ष तो मानो अकाल या अर्धअकाल की स्थिति का सामना करती आई है। पीने के पानी की जहाँ समस्या हो, वहाँ सूखे खेतों तक पानी पहुँचाने की कल्पना कैसे होती? 1960 से 1995 के दौरान गुजरात की जनता लगातार पानी की समस्या का शिकार बनती रही। फिर भी स्थिति यह रही कि समस्या से स्थायी निजात दिलाने वाला कोई हल खोजने की बजाय संबद्ध समय में पानी की समस्या के निवारण के लिए कामचलाऊ रास्ते ही खोजे जाते रहे। इस कामचलाऊ हल का मतलब है, अकाल के समय में गाँव में पीने के पानी के टैंकर पहुँचाना, करोड़ों रुपयों का मास्टर प्लान घोषित कर अकाल राहत के काम शुरू कराना और गरीब श्रमिकों को रोजगार देना। कभी-कभी इससे आगे बढ़कर कहीं-कहीं पुराने जर्जर हैंडपंपों की मरम्मत कराना या कहीं नए हैंडपंपों को मंजूरी देना। बस इतना ही। उस समय किसी शासक ने पानी की समस्या के स्थायी हल की दिशा में नहीं सोचा।

वास्तव में पानी की समस्या के स्थायी निवारण के लिए अनेक योजनाएँ लागू की जा सकती थीं, लेकिन न तो योजनाओं को लागू कर तेजी से पूर्ण करने का आयोजन किया गया और न ऐसी योजनाएँ शुरू ही की गईं। गुजरात की 18 लाख हेक्टेयर जमीन तथा करीब नौ हजार गाँव और 135 छोटे-बड़े शहरों को पीने के पानी की आपूर्ति करने की क्षमता रखनेवाली राज्य की महत्वाकांक्षी सरदार सरोवर योजना वैसे तो किसी भी शासक पक्ष के लिए महत्वाकांक्षी योजना थी। राज्य की तमाम सरकारें यह जानती थीं कि जब तक सरदार सरोवर योजना को तेजी से पूर्ण नहीं किया जाएगा, तब तक गुजरात में पानी की तंगी की समस्या का स्थायी निवारण नहीं होगा। इसके बावजूद वास्तविकता यह थी कि सरदार सरोवर योजना द्वारा गुजरात को तेजी से पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का बीड़ा पूर्व की किसी सरकार ने नहीं उठाया। यह बात और है कि 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सरदार सरोवर योजना का शिलान्यास किया था।

खेतों तक पहुँचा नर्मदा नीर

वर्षा की कमी के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र सिंचाई की भारी समस्या से जूझ रहा था। मध्य एवं पूर्व गुजरात में खासकर वडोदरा, पंचमहाल, भरुच, नर्मदा, खेडा, आणंद एवं अहमदाबाद जिले के भाल कस्बे में अपर्याप्त बारिश के कारण करोड़ों की कीमती फसल पानी के अभाव में झुलस जाने से कृषि अर्थव्यवस्था पर गंभीर चोट के हालात थे। दूसरी ओर वास्तविकता यह थी कि एक तरफ नर्मदा की मुख्य नहर में पानी बहने के बावजूद कई जिलों में नर्मदा जल सिंचाई के लिए देने में प्रबंधन का अभाव था। गुजरात अजीब विडंबना के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ नर्मदा का पानी मुख्य नहर में उपलब्ध था, दूसरी तरफ कीमती फसलें बिना पानी के झुलस रही थीं। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? मुख्यमंत्री ने तभी इस समस्या का हल करने की दिशा में विचार किया और खेतों तक नर्मदा का पानी पहुँचाने के लिए इंजीनियरों को निर्देश दिया।

खेतों तक सिंचाई के लिए नर्मदा जल न पहुँचाए जा सकने का कारण यह था कि इन क्षेत्रों में नर्मदा योजना की शाखा नहरें तब तैयार नहीं थीं। जब तक शाखा नहरों का काम पूरा नहीं होता, तब तक पानी पहुँचाया कैसे जाए? हाल यह था कि निकट भविष्य में नर्मदा शाखा नहरों का निर्माण पूरे होने की कोई संभावना भी नहीं थी। इन परिस्थितियों में नर्मदा जल सिंचाई के लिए खेतों तक पहुँचाने के अन्य कोई विकल्प खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था और यह विकल्प भी खोज निकाला गया। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नर्मदा जल की जरूरत थी, उन क्षेत्रों यानी आणंद और खेडा जिलों में 'मही सिंचाई योजना' के तहत मौजूदा नहरों से तथा अहमदाबाद जिले में खासकर बावळा, धोळका, साणंद, दसक्रोई तहसीलों में फतेवाड़ी कमांड एरिया की शाखा नहरों द्वारा नर्मदा जल खेतों तक पहुँचाया जा सकता था।

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब इन मौजूदा शाखा नहरों के माध्यम से खेतों तक नर्मदा जल पहुँचाने का प्रशासन को निर्देश दिया। इस प्रकार गुजरात के इतिहास में पहली बार सिंचाई के लिए सूखे खेतों तक नर्मदा जल पहुँचाने की शुरुआत हुई। वडोदरा जिले में सरदार सरोवर योजना की शाखा नहरों का काम कुछ हद तक पूर्ण हुआ था। इसीलिए इन क्षेत्रों में इन नहरों में नर्मदा का पानी छोड़कर खेतों तक पहुँचाया गया। खेडा और आणंद जिलों में मही शाखा नहरों के जरिए खेतों तक नर्मदा जल पहुँचा, तो अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी में नर्मदा जल प्रवाहित किए जाने के बाद फतेवाड़ी नहर से खेतों तक पहुँचाया जा सका। इससे पानी के अभाव में जल जाने वाली करोड़ों की फसल को बचाया साथ

में राज्य का कृषि उत्पादन नौ हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ के पार तक पहुँचा दिया।

वर्ष 2003-04 से गुजरात के अनेक जिलों में नर्मदा जल सिंचाई के लिए उपलब्ध होने के कारण कृषि उत्पादनों के मूल्योपार्जन में करोड़ों रुपयों की वृद्धि हुई।

कच्छ में नर्मदा जल

गाँवों और शहरों में नर्मदा का पानी पीने के लिए बहने लगा था, लेकिन कच्छ जिले में नर्मदा जल पहुँचाना तब की महत्वपूर्ण जरूरत थी। कच्छ वैसे भी वर्षा की कमी झेलने वाला क्षेत्र था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी परिस्थिति में पाइप लाइन से कच्छ में ठेठ पाकिस्तानी सीमा तक नर्मदा जल पहुँचाने के लिए प्रशासन को आदेश दिए। फलस्वरूप 18 मई, 2003 को कच्छ की सूखी धरती पर नर्मदा जलावतरण हुआ। 18 मई, 2003 का दिन कच्छी मांडुओं (कच्छ की जनता) के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय था। हजारों की संख्या में उमड़े कच्छी मांडुओं को तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी में जैसे भगीरथ के दर्शन हुए हों, उनका हर्षपूर्ण अभिवादन किया गया था। नर्मदा जलावतरण के उस सार्वजनिक कार्यक्रम में मोदी ने जब नर्मदा मैया का जलाभिषेक किया, तो कच्छी मांडुओं ने नर्मदा मैया के प्रत्येक बिंदु या नर्मदा मैया की धारा से तृप्त होने में जो उत्साह दिखाया, वह दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। कारण स्वाभाविक था। नर्मदा की आशा में जिंदगी बिताने वाली कच्छ की जनता को उनके जीते-जी नर्मदा मैया का कच्छ में अवतरण होगा, ऐसी उन्हें तनिक भी आशा नहीं थी। पर मुख्यमंत्री ने उनकी आशा को वास्तविकता में बदल दिया था। यह कार्यक्रम प्रतीकात्मक नहीं था। 18 मई, 2003 से अनेक गाँवों और चार शहरों में पाइप लाइन से नर्मदा जल का अवतरण हुआ था। इस अर्थ में कच्छ जिले के लिए यह एक ऐतिहासिक घटना थी। उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कच्छ की सूखी धरती के लिए नर्मदा का यह पानी कच्चा सोना साबित होगा।

नर्मदा के जल से बिजली उत्पादन

अक्तूबर 2004 से सरदार सरोवर में 110.64 मीटर तक नर्मदा का पानी बाँध में भरा जाने लगा। सरदार सरोवर योजना के इतिहास में यह पहला बिजली उत्पादन था, जो आज भी जारी है।

संघर्ष बाधक तत्वों से

सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई 121.92 मीटर तक पहुँचाने में गुजरात को जो संघर्ष करना पड़ा। इसका उल्लेख इसलिए जरूरी है, क्योंकि उस दौर में यदि नरेंद्र मोदी ने साम, दाम, दंड, भेद का एहसास न कराया होता, तो शायद गुजरात इस उपलब्धि से वंचित रह गया होता। सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई 121.92 मीटर तक बढ़ाने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में निर्णय लेने के लिए आरसीएनसीए की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में खलबली मच गई। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री डॉ. सैफुद्दीन सोज का रवैया बाँध के निर्माण को आगे बढ़ने से रोकने का था, तो दूसरी तरफ सरदार सरोवर योजना के विरोधी नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों ने बाँध की ऊँचाई 121 मीटर तक न पहुँचने देने के तमाम हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वजह स्वाभाविक थी। यदि बाँध की ऊँचाई 121 मीटर हो जाए, तो गुजरात के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता। इसीलिए इस निर्माण को आगे बढ़ने से रोकने के जो प्रयास हुए, उसके फलस्वरूप केंद्रीय जल संसाधन मंत्री डॉ. सैफुद्दीन सोज ने बड़बोलापन दिखाते हुए कह दिया कि पुनर्वास के काम संतोषजनक ढंग से नहीं हुए हैं। इसलिए बाँध की ऊँचाई और नहीं बढ़ने दी जाएगी। उनके इस कथन पर गुजरात में असंतोष और विरोध की आँधी फैली। यह वह दौर था, जब इस निर्णय का विरोध करने में गुजरात की जनशक्ति के लिए एकजुट होकर शांत शक्ति का परिचय कराकर बाँध की ऊँचाई बढ़ने के लिए संघर्ष शुरू करना जरूरी हो गया था। मुख्यमंत्री के लिए भी तब यह अप्रत्याशित कसौटी थी। सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे चुका था, पुनर्वास संबंधी कार्य संबंधित राज्यों में चल रहे थे, अचानक बाँध के निर्माण की मंजूरी की उपेक्षा करके निर्माण रोकने की चेष्टा कैसे बरदाश्त की जाती?

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीतिक चाल चलकर भारत सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। जब तक बाँध का काम आगे बढ़ने देने की मंजूरी की घोषणा नहीं होगी, तब तक उन्होंने अमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में 52 घंटे के उपवास की घोषणा की। अहमदाबाद में हजारों लोगों, साधु-संतों और सरदार सरोवर योजना के साथ जी-जान से जुड़े अनेक स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और समर्थन के बीच वे उपवास पर बैठ गए। दूसरी तरफ इसी अरसे में गांधी आश्रम-अहमदाबाद में तमाम राजनीतिक दलों के अग्रणियों, स्वैच्छिक संगठनों के अग्रणियों, व्यापारिक संगठनों और अन्य छोटे-बड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सांकेतिक उपवास शुरू कर नर्मदा विरोधी तत्वों के खिलाफ संघर्ष छेड़कर गुजरात की शांत शक्ति का परिचय कराया। इन सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समग्र घटनाक्रम में जो भूमिका निभाई, उसमें सुलझे हुए राजपुरुष के उनके व्यक्तित्व का अहसास गुजरात को फिर हुआ।

गुजरात में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए सरदार सरोवर योजना के साथ गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जलसंचय (बारिश के पानी का संग्रह) अभियान को भी प्रोत्साहित किया। वैसे गुजरात में जलसंचय अभियान वर्ष 2000 से ही शुरू हो चुका था। लेकिन इसमें तेजी आई नरेंद्र मोदी के शासन में। जब राज्य की छोटी-बड़ी नदियों पर बड़े-बड़े चेकडेम के निर्माण की शुरुआत हुई।

सरदार पटेल सहभागी जल संचय योजना के तहत गाँव-गाँव तटबंध निर्माण के अलावा नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र की वर्षों से सूखी-सपाट

रहनेवाली नदियों पर श्रृंखलाबद्ध बड़े तटबंधों का विचार रखा। आरंभिक चरण में सिंचाई विभाग के तहत जल संसाधन विकास निगम को इस प्रकार की विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपकर वर्ष 2003-04 और 2004-05 में इन नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू हुआ।

वास्तविकता यह है कि जनशक्ति को जगाने पर जोर देने की उनकी विशिष्ट शैली में प्रोत्साहित करने का उनका यह दृष्टिकोण था। सामान्यतः बहुत कम राजपुरुषों में यह दृष्टिकोण देखा जाता है। वरना किसी भी योजना के अच्छे परिणाम लाने के लिए उसमें जनशक्ति को प्रोत्साहित करने की मानसिकता कहाँ देखने को मिलती है? यहाँ बात ही अलग थी।

वर्ष 2000-01 से राज्य में प्रज्वलित जलक्रांति की ज्योति पिछले छह वर्षों के दौरान वर्ष-दर-वर्ष अधिक प्रज्वलित होती गई। आज नतीजा यह है कि गुजरात में हजारों तटबंधों के जरिए लाखों घनमीटर पानी का भूमिगत संग्रह हुआ है, दूसरी ओर राज्य की अनेक सूखी नदियों को पुनर्जीवन मिला है।

मोदी ने जल संचय योजना को जो नया आयाम दिया या नदियों को श्रृंखलाबद्ध तटबंधों के जरिए पुनर्जीवित करने के लिए, जो चिंतन किया, वह बिल्कुल स्पष्ट था। जब अच्छी से अच्छी बरसात हो, तब तमाम जलाशय पानी से लबलाब भरें। लेकिन जलाशय भरने के बाद बाकी का तमाम पानी समुद्र में बह जाए...? इस स्थिति का हल होना ही चाहिए—जलाशय भी भरें और नदियाँ भी बारह माह बहती रहें, तभी पानी की समस्या का हल मिल सकेगा। इस उद्देश्य से आयोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप पहली बार सूखी नदियाँ पुनर्जीवित हो सकीं। यह आयोजन यह बताने के लिए था कि जलाशय भरने के बाद अतिरिक्त पानी या उसकी एक भी बूँद समुद्र में नहीं जाने देनी है। इसी कारण बाँध भी छलके और नदियाँ भी छलकीं।

जल संचय से लाभ

जनभागीदारी सरदार पटेल सहभागी जल संचय योजना के अलावा अन्य योजनाओं के तहत आज सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात तथा पूर्व गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में लगभग एक लाख से भी अधिक तटबंध बनने के कारण भूमिगत जल स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तटबंधों के जरिए जल संग्रह के कारण इन क्षेत्रों के हजारों कुओं में साल में कई दिनों तक न्यूनतम 15 मीटर से अधिकतम 30 से 35 मीटर के स्तर तक जल को छलकते देखा गया। गुजरात के इतिहास में यह आश्चर्यजनक घटना है। सौराष्ट्र तथा उत्तर गुजरात के औसत किसान के लिए भूमिगत जल स्तर की यह वृद्धि भले आश्चर्यजनक नहीं हो, लेकिन हर्षित करनेवाली जरूर है। गरमी और ठंड में भी जो कुएँ रीते रहते हों, उन कुओं में गरमी में दो फसलें लेने के बाद भी यदि पानी दिखाई दे, तो किस किसान के दिल में खुशी नहीं होगी!

जल संचय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की एक नई दिशा खुली। पहला परिणाम यह आया कि गाँव छोड़कर धंधे-रोजगार की तलाश में शहर की तरफ दौड़ने वाले लोग फिर अपने गाँव लौटने लगे हैं।

बिजली समस्या का निदान

तटबंधों के कारण सिंचाई और पेयजल की दिशा खुली है, साथ ही बिजली की समस्या के निवारण की एक नई दिशा भी मिली है। खासकर उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में जल संचय से बिजली की समस्या के निवारण की एक नई दिशा बनी है। साबरकांठा तथा बनावकांठा जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में तटबंधों के कारण भूमिगत जल स्तर लगातार ऊपर आ रहा है, इससे कुओं में पानी की सतह तेजी से ऊपर आ रही है। औसत किसान आज भूमिगत पानी खींचने के लिए बिजली पर होने वाले खर्च से मुक्त है।

राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में जल संचय से चमत्कारिक परिणाम आए हैं। एक समय सामान्य झोंपड़ी में रहनेवाला आदिवासी अच्छे पक्के मकान में रहने लगा है। पक्के मकान और आसपास ही खेत में लहराती कपास, गेहूँ, रायडा या अरंडी की फसलें और उसकी आय से हर्षित आदिवासी किसान खुशी-खुशी कहता है, घर के आँगन में छलकते कुएँ और खेतों में पानी मिलने से अब गरीब भी मानो राजा बन गया है। घर में अच्छे-बुरे प्रसंग के समय किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता।

गुजरात में पानी की समस्या के स्थायी निवारण के लिए 'सुजला-सुफलाम्' योजना के तहत जल संचय, कच्ची स्प्रेडिंग, सुजलाम-सुफलाम कैनाल द्वारा जल संचय, तालाब गहरीकरण, भूमिगत पाइप लाइन से नर्मदा जल से उत्तर गुजरात के जलाशयों को भरने, आदिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा स्थापित करना, कच्छ जैसे क्षेत्र में क्षारीकरण समस्या दूर करने के लिए आड़बंध, ऐसी अनेक योजनाओं के पूर्ण होने से गुजरात में किसानों के लिए सिंचाई सुलभ हुई है। गुजरात के कृषि विकास में ऐसी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

एक तरफ मुख्यमंत्री ने नदियों पर श्रृंखलाबद्ध तटबंध निर्माण अभियान शुरू किया, जहाँ तटबंध संभव नहीं हैं, वहाँ बरसाती जल को, विशेषकर बारिश के मौसम में जब बारिश की तीव्रता कम होती है, ऐसी बारिश को जलप्रवाह में बह जाने से रोकने के लिए बोरी बाँध का एक नया प्रयोग मोदी ने प्रशासन को सुझाया। किसी भी प्रकार के खर्च के बिना जितना पानी जहाँ रोका जा सके, उससे फायदा ही होने वाला है। एक सामान्य सीमेंट या खाद की खाली थैली में रेत भर कर पाँच बाँध बना दो, तो पानी को एक छोर से, दूसरे छोर पर जाने में पाँच घंटे लगेंगे और इन पाँच घंटों में जो पानी जमीन में उतरे, उतना अतिरिक्त मुनाफा है।

नरेंद्र मोदी ने कृषि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के साथ ही कृषि के विकास के लिए शिक्षा, अनुसंधान और विस्तारण पर जोर दिया। उनकी सोच अलग थी। कृषि भारतवर्ष की संस्कृति है। साथ ही विज्ञान भी है। इसलिए कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों का समन्वय किया...यदि कृषि विज्ञान है तो कृषि वैज्ञानिकों के जरिए खेतों तक पहुँचना ही चाहिए। उनका कहना था कि जब तक वैज्ञानिक अनुसंधान खेत

तक नहीं पहुँचते, तब तक ये व्यर्थ ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2002 में जब जाना कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के पास 700 से अधिक कृषि वैज्ञानिक हैं, तब उन्हें लगा कि ये वैज्ञानिक यदि खेतों में जाएँ, तभी किसानों की सच्ची सेवा होगी। इसीलिए आणंद में वर्ष 2003 में आयोजित दीक्षांत समारोह में मोदी ने कहा था कि वैज्ञानिकों की मेहनत जब तक किसानों तक नहीं पहुँचती, तब तक अनुसंधानों की यह प्रक्रिया सार्थक नहीं हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आप वर्षों से खेती के लिए नए-नए प्रयोग करते हैं, नए-नए अनुसंधान करते हैं, बीज की नई-नई किस्में खोजते हैं। मैं मानता हूँ कि ये सब आप किसानों के लिए करते हैं।

खेतों में प्रयोगशाला

मुख्यमंत्री की यह भावना स्वाभाविक थी। सामान्यतः कृषि वैज्ञानिक पूरे दिल से खेती के लिए अलग-अलग अनुसंधान करते हैं, परंतु लैबोरेटरी में होने वाले अनुसंधान शायद ही खेतों तक पहुँच पाते थे। मूल्यवान अनुसंधान यदि खेतों तक नहीं पहुँचें, तो वे किस काम के? प्रयोगशाला और खेत की वास्तविकता अलग ही होती है। इसका मतलब यह नहीं कि लैब में होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों का खेत की व्यावहारिकता का कोई आधार नहीं होता। अधिकांशतः वास्तविक और व्यावहारिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर अनुसंधान होते हैं, लेकिन यह बात उतनी ही सही है कि वर्ष 2003 तक वैज्ञानिक अनुसंधान खेतों तक नहीं पहुँचते थे। इसीलिए मुख्यमंत्री ने राज्य के कृषि वैज्ञानिकों को एक नया नारा दिया—‘लैब टू लैंड’। यानी लैबोरेटरी में होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान खेतों तक पहुँचने चाहिए। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक लैबोरेटरी से बाहर आकर खेत में जाएँ और वास्तविक परिस्थिति का अभ्यास कर अनुसंधान करें तथा अनुसंधान खेतों तक पहुँचने अवश्य चाहिए। वैज्ञानिक की बुद्धि और किसान की सूझ-बूझ में समन्वय यदि हो जाए, तो सोने में सुहागा। इसीलिए नरेंद्रभाई ने एक नया विचार रखा। आज यह विचार साकार भी हुआ है।

कृषि महोत्सव के तहत जो कामकाज शुरू किए गए हैं, उसमें कृषि किट्स का वितरण, कृषि की सज्जी पद्धति का मार्गदर्शन, वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण, फसल योजना में बदलाव, पशु संवर्धन, जल संचय, बाड़ी योजना, गोबर बैंक और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने की व्यवस्था, तहसील मुख्यालय पर कृषि शिविर, पंचवटी योजना तथा ग्रामवार फसल आयोजन जैसे मुद्दे मुख्य हैं।

कृषि महोत्सव के आयोजन के कारण दक्षिण गुजरात के वलसाड, डाँग जैसे आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को बहुत फायदे हो रहे हैं। आदिवासी किसानों को कौन समझाता कि खेती का सही तरीका क्या है? उन्हें कौन समझाता कि जल-संचय से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है! उन्हें कौन समझाता कि यदि पशु संवर्धन किया जाए, तो पशुओं की दूध उत्पादकता बढ़ेगी। जो आदिवासी किसान दो जून की रोटी को तरसता हो, उसमें खेतीबाड़ी या बागबानी या पशुपालन की किट खरीदने की क्षमता कहाँ हो सकती है? और ऐसे असंख्य किसानों को यदि कृषि महोत्सव से लाभ मिले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?

इस प्रकार, गुजरात ने वर्षा आधारित खेती के स्थान पर विभिन्न उपायों से सिंचाई की सुविधा स्थापित की। उसके साथ ही कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा व विस्तार की जो प्रक्रिया लागू की, इससे कृषि क्षेत्र में चमत्कारिक नतीजे मिले हैं। गुजरात यदि कृषि क्षेत्र में देश भर में अग्रणी राज्य बना है तो इसका यही रहस्य है।

कन्या शिक्षा पर जोर

राज्य में शिक्षा की जो मुख्य समस्या रही, वह कन्या शिक्षा और साक्षरता दर में कमी थी। नरेंद्र मोदी ने कन्या शिक्षा की जरूरत पर बल देकर जो आयोजन किया, उसके फलस्वरूप पिछले पाँच वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में खासकर कन्या शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए वर्ष 2003-04 से कन्या शिक्षा रथयात्रा तथा शाला प्रवेशोत्सव का अनूठा आयोजन शुरू किया। इस अभियान से पिछले एक दशक में गुजरात के स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रवेश दर तथा कन्या शिक्षा में भारी वृद्धि हुई है।

कन्या शिक्षा रथयात्रा का अभियान अनूठा साबित हुआ है। कृषि महोत्सव की तरह इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री, जिला प्रभारी, सचिव, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, आईपीएस, आईएफएस, सचिवालय अधिकारी, शिक्षा सहित अन्य विभागों के अधिकारी जुटते हैं। सभी कन्या शिक्षा और प्रवेशोत्सव की सामाजिक सेवा की भावना से सक्रिय योगदान देने के लिए तपती गरमी में गाँव-गाँव कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम को हर वर्ष बहुत सफलता मिलती रही है। कन्या शिक्षा रथयात्रा के कारण निरक्षर अभिभावक भी शिक्षा, खासकर कन्या शिक्षा के लिए जाग्रत् बने। कन्या शिक्षा रथ के लिए प्राथमिक स्कूल में प्रवेश योग्य तमाम बच्चों और उसमें भी कन्याओं को स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है। उसके साथ ही स्कूल छोड़ गए बच्चों को पुनः स्कूल में प्रवेश दिलाने का कार्य भी किया जाता है। कन्या शिक्षा रथयात्रा में सरकार की कई योजनाओं की जानकारी तथा समझ के अलावा दिन-प्रतिदिन घटते महिला-पुरुष अनुपात और असमान जन्म दर को संतुलित करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या व बेटी बचाओ के लिए जागृति लाने के प्रयास किए गए। कन्या भ्रूण हत्या के कारण तथा कन्या शिक्षा के अभाव के कारण जो हालात पैदा होते हैं, उससे पैदा होने वाली सामाजिक समस्याओं से भी गाँववालों को अवगत कराया जाता है। कन्या शिक्षा रथयात्रा में सांसद, विधायक तथा जिला, तहसील, पंचायत पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। चालू वर्ष में भी कन्या शिक्षा व विद्यालय प्रवेशोत्सव के तहत 15-16 जून के दौरान समग्र राज्य के तमाम क्षेत्रों में कन्या शिक्षा रथयात्रा का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री स्वयं एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि भिक्षुक बनकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए गाँव-गाँव जाते हैं। यह कोई

छोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जिस गाँव में जाते हैं, वहाँ शिक्षा की अलख जगाते हैं। उपस्थित जनसमुदाय के सामने याचना अपनी विशिष्ट शैली में करते हैं। शैली इतनी प्रभावी होती है कि उपस्थित समुदाय में जिन अभिभावकों के बच्चे स्कूल में प्रवेश के लायक होते हैं, वे उनकी बात हर्ष से स्वीकार कर लेते हैं।

ई-गवर्नेंस

सामान्य जनसमुदाय को प्रशासन में सुधार की अनुभूति खासकर राजस्व विभाग के कामकाज से होती है। ग्रामीण, तहसील या जिला स्तर पर राजस्व विभाग के अधीनस्थ कार्यालय किस तरह काम करते हैं, उस पर प्रशासन की छवि आधारित होती है। गाँव या शहर के नागरिकों को जमीन संबंधित दस्तावेजों के लिए तहसील या जिला कलेक्टर के कार्यालय में अक्सर आना-जाना पड़ता है। इन दोनों कार्यालयों का कामकाज प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को छूता है। यह कामकाज जितना तेज हो, जितना सुलभ हो, उतनी ही प्रशासनिक कामकाज की छवि जनमानस में सुधरे। नरेंद्र मोदी ने अपने बारह वर्ष के शासन के दौरान इस बात को केंद्र में रखकर प्रौद्योगिकी के जरिए इस विभाग के कामकाज को अधिक परिणामदायी और प्रभावी बनाने की कोशिश की। इस उद्देश्य से अनेक प्रकार की योजनाएँ लागू की गई हैं। ई-गवर्नेंस जैसा नया शब्द प्रयोग भी गुजरात की जनता ने इसी समयावधि में सुना।

राज्य के प्रशासनिक ढाँचे में सबसे पुराना विभाग है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा अनेक प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावी व परिणामदायी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग ग्रामीण स्तर के सुदूरवर्ती नागरिक तक विस्तृत है। राज्य में भूमि के प्रत्येक टुकड़े का मापन हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि संबंधी विवरण दर्ज किए जाते हैं। उचित ढंग से एकत्र की गई जमीन संबंधी बुनियादी जानकारी, फसल पद्धति, सिंचाई अनुसंधान, बुवाई क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र, जुताई अधिकार, स्वामित्व अधिकार, भू-राजस्व तथा भूमि तब्दीली आदि विवरण सतत प्रक्रिया के तहत एकत्र किए जाते हैं और अद्यतन भी किए जाते हैं।

भूमि रिकॉर्ड, भूमि मापन, भू-राजस्व, भूमि प्रबंधन, सर्वे सेटलमेंट, अधिकार पत्र, भूमि अनुदान, भूमि अधिग्रहण, संपत्ति तब्दीली, मूल्यांकन, दस्तावेज पंजीकरण, स्टॉप ड्यूटी, कृषि भूमि शीर्ष मर्यादा, भूमि उपभोग रूपांतरण, आपदा प्रबंधन आदि राजस्व विभाग के मुख्य कार्य हैं। राजस्व विभाग नागरिकों की संवेदना और अपेक्षाओं की कद्र करता है।

राजस्व विभाग का आधुनिकीकरण

ई-धरा का अर्थ है कंप्यूटरीकृत लैंड रिकॉर्ड प्रबंधन। उसके मुख्य अंश देखें, तो ई-गवर्नेंस का उत्कृष्ट मॉडल, स्वच्छ सटीक सुनियोजित भूमि रिकॉर्ड, विकासशील टेक्नोलॉजी का लाभ सुदूरवर्ती ग्रामीणों तक पहुँचाने का प्रयास, जनसेवा में गति और सुशासन तेज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य बातें हैं। ई-धरा कार्यक्रम लागू कर राजस्व विभाग ने भूमि प्रबंधन क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ई-धरा कार्यक्रम के तहत राज्य के तमाम 225 तहसील मुख्यालयों पर ई-धरा केंद्र कार्यरत हैं। जमीन दफ्तर की स्वच्छ, सटीक व कंप्यूटरीकरण की त्वरित और सरल उपलब्धि के लिए सुविधा का निर्माण हुआ है। राजस्व विभाग ने 15 अगस्त, 2004 से हस्तलिखित खाता-खतौनी प्रणाली बंद करके मात्र कंप्यूटरीकृत प्रति को मान्यता दी है। राज्य की जनता को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ राज्य के 98 लाख 7/12 के रिकॉर्ड 56 लाख 8-अ के खाते सहित कुल 1.54 करोड़ लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किए गए हैं।

ई-ग्राम-ग्राम पंचायत कंप्यूटरीकरण

गुजरात में पंचायत विभाग ने जो महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं, उनमें ई-ग्राम विश्व ग्राम योजना शामिल है। गुजरात के गाँव विश्व समुदाय की पंक्ति में आ सकें, इसके लिए लोगों के जीवन में कंप्यूटर के जरिए सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंप्यूटर से जीवंत शहरों की माफिक गुजरात का गाँव भी पीछे न रहे, यही इस योजना का उद्देश्य है। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत को सचिवालय-गांधीनगर के साथ कंप्यूटर की मदद से नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध ई-सेवा जैसी ई-सेवा ग्राम पंचायत में देने के राज्य सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उनका मूल्य आज के आधुनिक युग में बहुत बढ़ जाता है। ग्रामीण स्तर पर 12,151 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर से ई-सेवा देने की सुविधा समग्र देश में मात्र गुजरात में ही है। इस अर्थ में गुजरात गाँव में ई-सेवा देने वाला देश का एकमात्र राज्य है। कुल 13,693 ग्राम पंचायतों में से 12,151 यानी लगभग 88.74 फीसद ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो अभूतपूर्व उपलब्धि है। प्रथम चरण में मुख्यतः ई-ग्राम से जन्म-मृत्यु का प्रमाण-पत्र, आय का प्रमाण-पत्र, जाति का प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र आदि तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के फॉर्म, आवेदन-पत्रों की उपलब्धता संभव हुई है।

इस कार्य के लिए जिला पंचायतों और 224 तहसील पंचायतों में से 222 तहसील पंचायतों को गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया है। सूचना के प्रचार-प्रसार और पंचायतों के सदस्यों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सेटैलाइट आधारित डायरेक्ट डिजिटल रिसेप्शन सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक तहसील पंचायत कार्यालय में जरूरी सूचना एवं पंचायत के लेखा के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए टच स्क्रीन कियोस्क से लैस तहसील सूचना केंद्र की व्यवस्था की गई है। ई-प्राइमा सॉफ्टवेयर के जरिए पंचायतों के लेखा की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण स्तर पर किसानों को 7/12 और 8-अ के दस्तावेज आदि की सूचना तहसील/जिला स्तरीय सर्वर पर से ग्राम पंचायत से देने की व्यवस्था की गई है। साइबर सेवा के तहत गाँव के एनआरजी/एनआरआई के साथ इंटरनेट के उपयोग से ग्रामीण जनों

द्वारा प्रसंगवश बातचीत व संपर्क तथा इंटरनेट द्वारा कृषि शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधी जानकारीयों ग्राम पंचायत में उपलब्ध होती हैं। इसके साथ ही ई-ग्राम पंचायत में बिजली व टेलीफोन बिल, बीमा तथा डाक सेवाएँ देने की भी व्यवस्था की गई है।

पंचवटी योजना

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ ग्रामीण समस्याओं के निवारण के लिए ई-धरा प्रोजेक्ट के जरिए ग्राम पंचायतों को ढाँचागत सुविधा युक्त बनाने का अभियान शुरू किया, तो दूसरी तरफ गाँव की पर्यावरण समृद्धि बढ़ाने व उसके साथ सामाजिक असमानता को दूर करने के विचार के साथ 'तीर्थग्राम' और 'पंचवटी' योजनाएँ भी लागू कराईं। सामान्यतः शहरों में बच्चों के खेलने-कूदने के लिए बाग-बगीचों की सुविधा होती है, परंतु गाँवों में पर्व-त्योहारों में बच्चों के खेलने व बड़ों के लिए शांति से बैठकर समय गुजारने के लिए बाग-बगीचे जैसी सुविधाओं के निर्माण की योजना लागू की गई। पंचायत विभाग आज राज्य के अनेक गाँवों में यह योजना लागू कर चुका है। नरेंद्र मोदी ने राज्य के गाँवों में पंचवटी योजना का शुभारंभ करते हुए कहा था, "हमारी प्राचीन संस्कृति के उद्गम से पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। हमारे धर्मग्रंथों, शास्त्रों और वेदों में भी पेड़ों की महिमा और उसकी उपयोगिता हमेशा समझाई गई है। हमारे वेदों में पीपल के पेड़ को समग्र ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है, इसीलिए व्रत-त्योहार के समय महिलाएँ व कन्याएँ उसकी परिक्रमा कर अपना तप पूरा करती हैं। पीपल पर बैठे पक्षियों को आत्मा तथा परमात्मा का स्वरूप माना गया है।" कुछ इसी तरह की कल्पना के साथ पेड़ों के महत्त्व व पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर राज्य में पंचवटी योजना साकार हुई।

राज्य की ग्रामीण जनता में विविधतापूर्ण लोक संस्कृति बुनी हुई है। गाँवों की सीमाओं के क्षेत्र वन-संपदा से भरपूर थे। गाँवों के बच्चे पेड़ों की छाया में झूले का और पर्यावरण का स्वच्छंद आनंद लेते थे, परंतु कालांतर में उस समृद्धि के लुप्त होने के कारण समग्र परिस्थिति का ग्रामीण जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; लेकिन इस समस्या के निवारण के लिए, खासकर गाँवों के परती क्षेत्र गाँव के लोगों के सहयोग से नवपल्लवित हुए और गाँव में ही वृक्षाच्छादित बगीचों की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए पंचायत विभाग ने यह योजना लागू की। पंचवटी योजना के तहत गाँव में उपलब्ध बगीचों में लगाने के लिए पेड़ों का चयन भी है? पीपल, बरगद, हरड़, बेल, अशोक तथा अनेक फलदार पेड़ इन बगीचों में लगाए जाने लगे हैं। सामान्यतः इस योजना के तहत बनने वाले बगीचे खुली जगह में एक हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र वाली समतल जमीन पर बनाए जाते हैं। यह बगीचा मेरा और मेरे गाँव का है, यह भावना लोगों में जाग्रत करने के लिए जनसहयोग के तहत 50 हजार रुपए की राशि भी निर्धारित की गई है। इस जगह में शौचालय-बाथरूम की सुविधा भी तय की गई है, तो फिर बिजली बिना कैसे चल सकता है? अर्थात् बिजली या उसके विकल्प के रूप में सोलर लाइटिंग की सुविधा भी पंचवटी योजनांतर्गत बने बगीचों में उपलब्ध कराने का इरादा शामिल किया गया है। अनेक बगीचों में ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पंचवटी-बगीचे के आसपास यदि गाँव-तालाब हो, तो नौका-विहार और उसके लिए जरूरी सुविधाएँ भी विकसित करने का प्रावधान इस योजना में है।

लोक भागीदारी के विचार को केंद्र में रखकर इस योजना में ग्राम पंचायत ने लोक भागीदारी के 50 हजार रुपए भरने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार एक लाख रुपए की सहायता देती है। लोक भागीदारी का सहयोग संसाधनों या वस्तुओं के रूप में देना होता है। नकद भरने वाली ग्राम पंचायत को प्राथमिकता मिलती है।

तीर्थग्राम योजना

जिस प्रकार पंचवटी योजना की परिकल्पना बेजोड़ है। ठीक वैसी ही खास पंचायत विभाग की योजना 'तीर्थग्राम योजना' है। गाँव हो या शहर, दौंव-पेंच, फौजदारी अपराध, पुलिस शिकायत, नशाखोरी, चोरी, अत्याचार या इसी प्रकार की अन्य बुराइयाँ आज सामाजिक जीवन में देखने को मिलती हैं, लेकिन राज्य के अनेक गाँव ऐसे भी हैं, जहाँ कुछ वर्षों से न पुलिस में शिकायत हुई और न एफआईआर दर्ज हुई है। कोई गंभीर अपराध भी नहीं हुआ है। गाँव में प्रवेश करनेवाले अतिथियों को लगे कि यह कोई अनोखा गाँव है। गाँव में भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, शांति और सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थग्राम का विचार लोगों में फैलाया है। सन् 2004-2005 से पंचायत विभाग ने यह योजना लागू की। इस योजना के तहत गाँव के चयन मानदंड भी तय किए गए। ग्राम पंचायतों के चुनावों में सर्वसम्मति से निर्विरोध घोषित पंचायत को 'समरस ग्राम' घोषित किया जाता है और ऐसे समरस गाँव को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। पिछले पाँच वर्षों में अपराध न हुए हों, ऐसे गाँवों को तीर्थग्राम और विकास की योजनाओं में प्रमुखता दी जाती है। मादक पदार्थों का उत्पादन, बिक्री या सेवन ऐसे गाँवों में नहीं होता है।

तीर्थग्राम के चयन के जो दूसरे मापदंड हैं, उनमें स्वच्छता का उचित मापदंड, कन्या शिक्षा की ऊँची दर तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के ड्रॉप आउट की निम्न दर, सामाजिक सद्भावना से विकास तथा सामाजिक विवादों का अभाव, चर्चा तथा संवाद से विवाद का निपटारा, गाँव के धार्मिक स्थानों और गाँव में विवाद का बिलकुल अभाव, गाँव के अन्य क्षेत्रों में प्राप्त प्राथमिक सुविधाओं जैसी सुविधाएँ गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में भी उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसे मापदंड निर्धारित हुए हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत ग्रामीणों द्वारा तिथियाँ दर्ज कराने में भागीदारी, स्कूली कमरे, विद्यालक्ष्मी बॉण्ड, शिक्षा संसाधन आदि की खरीदारी में भागीदारी, अस्पृश्यता निवारण का कड़ाई से अमल, जल संचय योजना के तहत कृषि तालाब, बोरी बाँध बनाने में उल्लेखनीय कार्य को भी इसके मापदंड में शामिल किया गया है। पंचायत विभाग ने इस योजना का संचालन करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तीर्थग्राम चयन के लिए चयनित मापदंड तय

करने के लिए मार्गदर्शक प्रणाली पंचायत विभाग ने लागू की है। इस प्रकार लोक भागीदारी से गाँवों को आधुनिक व सुदृढ़ बनाने की तैयारी हो चुकी है। देश के विकास की इकाई गाँव है। 'गाँव विकसित, तभी देश विकसित'। इस मंत्र को साकार करने के लिए निश्चित प्रतिबद्धता के साथ हुई कोशिशें नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं।

चिंता नमक कामगार परिवारों की

मछुआरे और आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी ने विशेष ध्यान दिया। नरेंद्र मोदी मछुआरों की समस्याओं पर कहते हैं —“एक सप्ताह आप नमक से वंचित रह जाएँ, तो आपकी और मेरी कैसी दुर्दशा होगी, उसका अंदाजा मुझे और आपको जरूर होगा। मेरी और आपकी जिंदगी को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए समुद्र किनारे जीने वाले हमारे नमक कामगार अपने शरीर की परवाह किए या अपने परिवार के सुख-दुःख की परवाह किए बिना हमारे लिए नमक बनाते हैं। फिर नमक बनाने वाले कामगारों की चिंता करने की हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? और इसीलिए ‘सागरखेडू प्रोजेक्ट’ में मैंने गुजरात के नमक कामगार परिवारों की चिंता भी जोड़ने का निश्चय किया है। उन लोगों को मोबाइल अस्पताल मिले, मोबाइल अस्पताल रेगुलेटर उनके घर पहुँचकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करे, नमक कामगार परिवारों के बच्चे पढ़-लिख सकें, इसके लिए उन्हें आवास की सुविधा के साथ, पढ़ाई के लिए उनके बच्चों को तमाम व्यवस्था मिले, उसका विचार किया है।”

नरेंद्र मोदी जब सागरखेडू के सर्वांगीण विकास पैकेज की घोषणा करते हैं और उसके लिए योजना भी बन रही हो, तो नमक कामगारों की समस्या कैसे अछूती रह सकती है? इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्य के नमक कामगारों के सर्वांगीण विकास की इच्छा व्यक्त की—

“नमक कामगार परिवारों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत ही तमाम चिंता का काम राज्य सरकार ने अपने सिर लिया है।”

10 सूत्री कार्यक्रम

वनबंधु कल्याण के लिए पाँच लाख परिवारों के वास्ते रोजगारपरक कार्यक्रम चल रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करना, पशुपालन तथा डेयरी उद्योग एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ बढ़ाना, आदिजाति युवकों को गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण देकर, उनकी आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी कुशलता बढ़ाकर नए रोजगार में उन्हें जोड़ना, इसके अलावा उनके परिवारों, जिनकी मुखिया महिला हों, उन्हें आदिजाति कल्याण योजनाओं में प्राथमिकता देना, इस योजना का इरादा है।

राज्य में गाँवों में रहनेवाली बेटियाँ पढ़ने के लिए दूसरे गाँव जाएँ, तो बस का पास मुफ्त मिलेगा। इस पर अमल शुरू हो गया है।

अमीरगढ़, दाँता के 52 हजार से अधिक आदिवासी बच्चों को आठ से दस रुपए मूल्य का दूध देने का प्रयास शुरू किया गया है। इसके चलते बच्चों के शरीर को जरूरी तमाम पोषक तत्व मिलते हैं। लगभग सात माह से यह प्रयोग शुरू किया गया है। इसका नतीजा यह है कि स्कूल में आदिवासी बच्चों की हाजिरी बढ़ी है। इतना ही नहीं, अमीरगढ़ दाँता के इन आदिवासी बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरा है। प्रत्येक बच्चा खिलने लगा है। आदिवासी बच्चे का स्वास्थ्य देखें, तो लगता है गुजरात का स्वास्थ्य दुरुस्त हो रहा है। क्या ये बच्चे मुझे वोट देने को हैं? 15-15 साल तक के इन बच्चों को मताधिकार नहीं मिलने का, यहाँ वोट की राजनीति की कोई बात ही नहीं है। यहाँ केवल छोटे-छोटे मासूमों की चिंता है, छोटे बालक और नौनिहालों की चिंता है और इसीलिए यह योजना आगे चलाई जा रही है।

15,000 करोड़ रुपए के पैकेज में आदिवासियों को अपना पक्का घर देना है। कोई भी आदिवासी ऐसा न रहे, जिसे पेड़ के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर होना पड़े। हर आदिवासी की झोंपड़ी में बिजली का कनेक्शन है। आदिवासी तहसील में एक आईटीआई की स्थापना हुई है। इस कारण आदिवासी युवाओं के काम में गति आई है। आदिवासी युवा मजदूरी से बाहर आकर स्वाभिमान से जी रहा है।

‘वनबंधु’ योजना ने सही अर्थ में गुजरात के आदिवासी पट्टे में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पानी, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, बागबानी, स्वास्थ्य, जंगल के अधिकार की लकड़ी, बाल स्वास्थ्य, भूमि पट्टे, सड़क मजबूतीकरण और बिजली यानी कोई भी क्षेत्र आज आदिवासी क्षेत्र में ऐसा नहीं है, जहाँ विकास की अनुभूति न हुई हो।

ग्रामीण विकास का राजमार्ग

वर्ष 2002 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी बार गुजरात का शासन सँभाला, तब उन्होंने ग्रामीण गुजरात की एक अभिनव कल्पना के साथ गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए पंचशक्ति के सान्निध्य में ग्रामीण विकास की अलख जगाई। उन्हें लगा कि शहर का नागरिक घरेलू उपभोग के लिए चौबीस घंटे श्री फेज बिजली पाता है, तो गाँव का नागरिक क्यों नहीं? यदि शहरों में बिजली के सहारे छोटे-बड़े उद्योग चलते हैं, तो गाँव में 24 घंटे श्री फेज बिजली से छोटे-छोटे गृह उद्योग क्यों नहीं विकसित हो सकते? खेती चौपट हुई और बिजली, रास्ते, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रोजगार की समस्या से जूझने वाले गाँव भी टूटे। इसका यदि निवारण करना है, तो इस सुविधा को गाँव को देना होगा और युद्ध स्तर पर देना होगा। अन्य सुविधाएँ तो गुजरात के गाँवों को मिलने लगी थीं, लेकिन घरेलू उपभोग के लिए चौबीस घंटे बिजली की बात तब नहीं बनी थी। वास्तव में ‘ज्योतिग्राम’ योजना गुजरात की एक महत्वाकांक्षी योजना ही नहीं, बल्कि राज्य के ग्रामीण विकास का राजमार्ग है। ग्रामीण गुजरात की जीवन डोर है।

गुजरात में एकमात्र ऐसी सरकार है, जो अपने राज्य के 18 हजार गाँवों व आठ हजार उप नगरों को चौबीस घंटे श्री फेज बिजली बिना कटौती पहुँचाती है। यह कठिन और असंभव लगने वाला कार्य भी सरकार ने सोच-समझकर अपने हाथ में लिया है, क्योंकि बिना बिजली के स्थिति की पीड़ा और वेदना को यह सरकार समझती है।

एकमात्र गुजरात में शहरों-महानगरों में भी बिजली सहज मिलती है और अब गाँवों में भी चौबीस घंटे बिजली मिलने लगी है। गाँवों में बिजली

ज्योतिग्राम योजना के तहत मिलने लगी है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों के रोजगार में पाँच गुना वृद्धि हुई है और छोटे धंधे-रोजगार के अवसर बहुत बढ़े हैं। ज्योतिग्राम योजना मात्र घरेलू उपभोग की बिजली या मनोरंजन की सुविधा मात्र नहीं है, अपितु गाँव की आर्थिक क्रांति के संदेश का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। गाँव की आर्थिक शक्ति के क्रांतिकारी प्रभाव गुजरात की अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे। गाँव और शहर के बीच का फासला खत्म होकर आधुनिक शिक्षा और ई-ग्राम से गाँव में विकास की तसवीर ही बदल गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सेवाएँ देने वाले चिकित्सक गाँव में स्थायी हो रहे हैं।

ज्योतिग्राम योजना छोटे आदमी की अंधकार की पीड़ा से जनमी है। गरीब ग्राम समाज के साथ संवेदना रखने वाली इस सरकार ने शहर व गाँव से बिजली का भेदभाव दूर किया है। ज्योतिग्राम से किसानों में ट्रांसफॉर्मर तथा खेती की मोटर का चलन अटका है और खड़ी फसल झुलसने से बची है। गाँव में चौबीस घंटे श्री फेज बिजली मिलने से कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धित रूपांतरण की प्रक्रिया से किसानों की आय में क्रांतिकारी बढ़ोतरी हुई है।

ज्योतिग्राम के प्रत्यक्ष लाभ

- घरेलू उपभोग व घरेलू उद्योग को चौबीस घंटे और खेती को उपयोगी आठ घंटे की सतत बिजली आपूर्ति।
- कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई।
- गाँवों में अर्थव्यवस्था सुधरी, अनियमितताएँ रुकीं।
- गाँव आत्मनिर्भर बने। रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए गाँवों को शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- राज्य में टी एंड डी लॉस तथा ट्रांसफॉर्मर फेल होने की दर में कमी।
- अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय कदम।
- बिजली चोरी रुकने के कारण आय में वृद्धि।
- उच्च गुणवत्तायुक्त निरंतर बिजली आपूर्ति से ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों का विकास।
- स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि।
- अधिक बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ।
- ग्रामीण क्षेत्र की जनता के शहरों की ओर पलायन पर नियंत्रण।
- ग्रामीण प्रजा के जीवन स्तर में सुधार तथा दिनचर्या के अनुरूप बिजली आपूर्ति की उपलब्धता।
- खेतीबाड़ी को पूर्वनियोजित समय पर नियंत्रित बिजली आपूर्ति, परंतु उच्च गुणवत्तायुक्त निरंतर बिजली आपूर्ति के कारण होने वाले पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के चलते भूतल जल संचय के भंडार में वृद्धि।
- बिजली की चीजों के बढ़ते उपभोग के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता में देश व दुनिया में घटने वाली घटनाओं की जानकारी में वृद्धि।
- प्राकृतिक आपदाओं के समय बिजली आपूर्ति का तेजी से पुनर्स्थापन, ज्योतिग्राम की रोशनी।

राष्ट्र में प्रथम ज्योतिग्राम योजना आरंभ में आठ जिलों में लागू की गई। इससे हासिल सफलता से प्रेरित होकर 17 नवंबर, 2004 से इसे समग्र राज्य में लागू किया गया। आज समग्र गुजरात ज्योतिग्राम योजना से झिलमिला रहा है।

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन शैली पहले से ही अनूठी रही है। समस्याओं का जड़ से स्थायी निवारण की उनकी कार्यशैली के कारण गुजरात में पिछले तेरह वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुरानी समस्याओं के निवारण में प्रशासन को आश्चर्यजनक सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। इतना ही नहीं, जटिल समस्याओं के निवारण में उन्होंने जनभागीदारी को जोड़कर विशिष्ट सूझ-बूझ दिखाई है।

ज्योतिग्राम योजना के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के बढ़ते उपभोग के कारण स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन, सरकारी योजनाओं और संबंधित आय वृद्धि के अवसरों के प्रति जागृति बढ़ी।

बढ़ती घरेलू सुख-सुविधाओं के कारण इस योजना के अमल के आरंभ में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक व आय वृद्धि संबंधी प्रवृत्तियों पर दिए जाने वाले समय में भारी वृद्धि हुई थी, जब कि रोजमर्रा के घरेलू कार्यों पर उपयोग होने वाले समय में करीब 26 फीसद की कमी आई थी।

औद्योगिक प्रवृत्तियाँ जैसे डायमंड पॉलिशिंग, प्रसाधन, एग्रो प्रोसेसिंग आदि को गति मिली। योजना के कारण 53 फीसद परिवारों को रात्रि के समय काम करने का अवसर मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देकर यह योजना वास्तव में गुजरात को प्रकाश की ओर ले गई है।

विकास व कचरा निष्पादन के नए रूप

सौ वर्ष में विश्व की जनसंख्या दो अरब से बढ़कर छह अरब हो गई है और गुजरात में तो चालीस फीसद आबादी शहरों में रह रही है, जो बढ़कर तेजी से 50 फीसद पर पहुँचेगी। इसके लिए शहरीकरण समस्या नहीं, बल्कि अवसर बनें, यही हमारा शहरी विकास-पथ रहनेवाला है। विकास की दिशा में नई पहल से अन्य को प्रेरणा मिलेगी। हमने गुलामी के कालखंड में कपड़ा उद्योग की प्रतिष्ठा पाकर अपनी सामर्थ्य साबित

की है। अब श्वेत क्रांति तथा हरित क्रांति के साथ डेयरी उद्योग में अग्रसर रहे हैं। शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 'वेस्ट से वेल्थ' बनाने तथा गंदे पानी की रिसाइलिंग कर सामाजिक ढाँचे के लिए उपयोगी बने, इस दिशा में गुजरात ने पहल की है। ज्योतिग्राम को शहरी क्षेत्र की तरह चौबीस घंटे श्री फेज बिजली गाँव को भी मिले। ऐसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्रांति कर शहरों की ओर जा रही ग्रामीण आबादी के पलायन को घटाने में भी गुजरात ने पहल की है। शहरी विकास में लोक भागीदारी को व्यापक और विशाल प्रतिसाद प्राप्त कर गुजरात ने विकास की दिशा में बड़ी छलाँग लगाई है।

नगर विकास की चुनौतियाँ

पिछले अनेक वर्षों से नगर के लिए सड़क, ठोस प्रवाही कूड़े की निकासी और जलापूर्ति जैसी सुख-सुविधाओं की महत्ता पहचान कर गुजरात राज्य ने 'नगर' यानी नल, गटर और रास्ते जैसी एकदम व्यावहारिक व्याख्या दी है। लोगों की गाँवों से शहरों की ओर दौड़ रोकने के लिए स्वस्थ ग्रामीण विकास की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत नगर के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की भी है।

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शितापूर्ण भावी विकास रणनीति के नक्शेकदम पर चलनेवाली वर्तमान राज्य सरकार ने इन दोनों मोर्चों पर दूरगामी सकारात्मक परिणामों का आश्वासन देने वाली उपलब्धियाँ हासिल की हैं। नगर पालिकाओं के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए वैचारिक प्रशासनिक सुधार, पेयजल योजनाएँ, विकास पथ जैसे नए आयोजन, ठोस कूड़े की निकासी तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण से नगरों को हरियाला बनाने जैसे श्रृंखलाबद्ध कदमों ने शहरी विकास को उपलब्धियों से लाद दिया है।

शहरों का कायापलट

पहले एक वर्ष के अंत में मुश्किल से 25 नगर नियोजन योजनाएँ बनने की ढीलीढाली स्थिति थी। अब शहरी विकास वर्ष के बाद वार्षिक करीब सौ नगर नियोजन योजनाएँ संभव हो पा रही हैं। प्रशासनिक सुधारों के फलस्वरूप संभव हुए डेवलपमेंट प्लान्स के कारण रियल एस्टेट डेवलपमेंट में गुजरात श्रेष्ठतम बना है। उपलब्ध कराई गई ढाँचागत सुविधाओं के कारण गुजरात का अतुलनीय विकास हुआ है। कंक्रीट वाले, मिट्टी वाले, रेती वाले व्यापारी, रोजगार, श्रमयोगी, सीमेंट, पत्थर के व्यापारियों को विश्वसनीय रोजगार का लाभ भी प्राप्त हुआ है।

124 नगर पालिकाओं ने 'समाधा' योजना स्वीकारी है। 24 नगर पालिकाएँ बिजली बोर्ड के कर्ज से पूर्णतः मुक्त हुई हैं। गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लियरेंस बोर्ड के प्रबंधन का भी प्रभावी नवीनीकरण किया गया है। विकास की प्राथमिकताओं में आपदा प्रबंधन भी शामिल है।

गौरव पथ

सड़कों के मामले में शहर की मुख्य सड़कों में से कम-से-कम एक सड़क को गौरव पथ के रूप में विकसित करने के इरादे से सरकार ने गौरव पथ के रूप में चुने रास्ते से तमाम अतिक्रमण हटाकर, पथ को हरियाली से भरपूर कर, समतल सड़क, फुटपाथ तथा स्ट्रीट लाइटों से परिपूर्ण किया है। गौरव पथ के दोनों ओर स्थित तमाम मकानों के एक समान कलर कोड तय कर लोगों के सहयोग से मार्ग को विशिष्ट रूप दिया है।

चिरंजीवी योजना

नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मोदी सरकार ने 'चिरंजीवी योजना' लागू की है, जिसे अपार सफलता और सराहना मिली है। इस योजना को सिंगापुर में 'वाशिंगटन पोस्ट' का 'एशियन इनोवेटिव अवॉर्ड' प्राप्त हुआ है।

'बेटी बचावो आंदोलन' के कारण महिलाओं की दर प्रति 100 पुरुष के पीछे 802 से बढ़कर 870 हो गई है। विद्यार्थियों के निःशुल्क मेडिकल चेकअप का काम हाथ में लिया जा रहा है और उन्हें डॉक्टरों उपचार तथा ऑपरेशन की सुविधा भी मुफ्त दी जाएगी।

4,400 आँगनवाडियों के तीन वर्ष के कम आयु के 10 लाख बच्चों को विटामिन ए-डी पोषाहार दिया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से प्रतिदिन 30,000 टन मल उपचार का काम भी हाथ में लिया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है।

मेडिकल टूरिज्म की संकल्पना सफल सिद्ध हुई है और अमदाबाद में प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान से विदेशी/एन.आर.आई. रोगी यहाँ आते हैं। नमक मजदूरों, मछुआरों, आदिवासियों तथा अंदरूनी क्षेत्रों के लिए 85 मोबाइल वैन डॉक्टरों सेवाओं के लिए दी गई हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए गए हैं। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रामदास ने घोषित किया था कि अगले बजट में 'गुजरात मॉडल' की 'चिरंजीवी योजना' सारे देश में लागू की जाएगी। मीडिया की एक खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार बी.पी.एल. परिवारों की गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव सुविधा मुहैया कराने के लिए गुजरात की तर्ज पर 'चिरंजीवी योजना' लागू करने पर विचार कर रही है।

नरेंद्र मोदी ने इस योजना के बारे में लिखा है कि गुजरात ने सबसे पहली बार महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए और अस्पताल में उन्हें निःशुल्क चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में 'चिरंजीवी योजना' लागू की। 'चिरंजीवी योजना' के परिणामस्वरूप माता और शिशुओं की संख्या में बड़ा सुधार आया है। नारी-शक्ति को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए वर्ष 2006 में 'नारी गौरव नीति' लागू की है।

नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से इस संबंध में जारी निर्देश हैं—

1. गर्भधारण के तुरंत बाद से ही शिशु की देखभाल शुरू की जानी चाहिए।

2. सुनिश्चित करें कि गर्भधारण की प्रारंभिक स्थिति में गर्भवती महिलाएँ नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएँ। गर्भावस्था के दौरान वे कम-से-कम तीन बार जाँच अवश्य कराएँ।
3. सुनिश्चित करें कि प्रसव स्वास्थ्य केंद्र में हो। यदि वहाँ संभव न हो तो सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षित दाई/नर्स द्वारा प्रसव संपन्न हो।

मातृ-वंदना योजना

‘मातृ-वंदना योजना’ जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु है। यह योजना बेहद सफल रही है। ‘मातृ-वंदना योजना’ में भी 23.80 करोड़ का प्रावधान है, इसके लिए गुजरात सरकार को पुरस्कार भी मिल चुका है।

इस योजना के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं—

- राज्य स्तर पर लोगों में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। नवजात शिशुओं की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है, इस के लिए तुरंत उचित कदम उठाने की जरूरत है।
- लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि बच्चे के जन्म से पूर्व तथा बच्चे के जन्म के पश्चात् किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।

बेटी बचाओ अभियान

भ्रूण-हत्या और लिंगानुपात पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया। भारत के समृद्ध राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या पंजाब में 798, हरियाणा में 819 और गुजरात में 883 थी। गुजरात में मोदी की पहल के बाद वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजे सकारात्मक रहे और बालिकाओं की संख्या गुजरात में 918 हो गई।

कुछ राज्यों ने इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया और इसे रोकने के लिए अनेक कदम उठाए। जिस प्रकार गुजरात में ‘बेटी बचाओ अभियान’ चलाया जा रहा है, उसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। देश में चार दशकों से सात साल से कम उम्र के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। सन् 1981 में 1000 बालकों पर 962 बालिकाएँ थीं। सन् 2001 में यह अनुपात घटकर 927 हो गया।

यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक समृद्धि और शिक्षा के बढ़ते स्तर का उस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रसव से पूर्व तकनीकी जाँच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है।

गुजरात की मोदी सरकार ने जीवन बचानेवाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकने का हरसंभव प्रयास किया है। कन्या भ्रूण-हत्या के खिलाफ कड़े कानून बनाकर पायलट परियोजना को गुजरात के पाँच जिलों में चलाया गया, जहाँ 22,163 शिशुओं का जन्म हुआ, जिनमें से मात्र 87 शिशुओं की मृत्यु का समाचार मिला है, अन्यथा जिनकी संख्या 812 हो सकती थी।

इस योजना के सफल होने के कारण अब इसे पूरे गुजरात राज्य में लागू करने की घोषणा की गई है, जिसकी प्रशंसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी की और पूरे देश में कार्यान्वित करने को कहा है।

भारतीय ग्रंथों में नारी की पूजा, देवी के रूप में होती आई है। गुजरात एक ऐसा राज्य है, जहाँ नारियों को वाकई पूजा जाता है। उनका सम्मान किया जाता है और उनके सशक्तीकरण के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किए गए हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या कन्या भ्रूण-हत्या के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता यहीं मिली है।

नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि ‘कन्या भ्रूण की हत्या करने के बजाय बेटी के जन्म को परिवार का गर्व मानो’। ‘बेटी बचाओ’ के साथ मोदी ने तमाम अभियान शुरू किए। गुजरात आज महिलाओं के लिए काम करने की सबसे सुरक्षित जगह बन गया है। राज्य में बी.पी.ओ. की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

इस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को कर्तव्य की तरह निभाई जाती है। वहीं अगर अन्य राज्यों में देखें तो कन्या भ्रूण-हत्या के साथ-साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की संख्या ज्यादा है।

करीब एक दशक पहले नरेंद्र मोदी ने ‘बेटी बचाओ’ अभियान शुरू किया था। साल-दर-साल मोदी ने समाज के हर तबके से कन्या के जीवन का महत्व समझने की अपील की। इसके साथ-साथ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वेबसाइट ‘बेटी बचाओ डॉट कॉम’ शुरू की। वेबसाइट के माध्यम से लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज करने का मंच प्रदान किया गया।

इसके माध्यम से ‘प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेकनीक (रेग्युलेशन ऐंड प्रीवेंशन ऑफ़ मिसयूज) अधिनियम-1994’ से लोगों को जागरूक करने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

ज्योतिग्राम योजना

प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाने हेतु नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना इतनी सफल रही कि विदेशों में भी इसका अनुकरण किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने गुजरात सरकार की ज्योतिग्राम योजना की प्रशंसा की है। यह सन् 2003 में शुरू

की गई थी और इसका उद्देश्य गाँवों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराना है।

कर्मयोगी अभियान

गुजरात में सरकारी कर्मचारियों में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा जगाने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई। यह कारगर साबित हुआ है। सभी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और आदर्श निर्देश संविधान की मर्यादा में दिए गए हैं। गुजरात में सरकारी कर्मचारियों को समाज-सेवक कहा जाने लगा है। उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि वे क्या करें और क्या न करें। कुछ निर्देश इस प्रकार हैं—

1. सदैव याद रखें कि आप सरकारी कर्मचारी और जनता के सेवक हैं। आपको सार्वजनिक राजकोष से वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाओं आदि के जरिए आपकी सेवाओं के बदले उचित प्रतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार आप सरकारी सेवक की परिभाषा में आते हैं। आप पर भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत किए गए प्रावधान लागू होते हैं।
2. राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को मुक्त, ईमानदार, भय-मुक्त तथा तटस्थ ढंग से सत्यनिष्ठा, समर्पण, प्रतिबद्धता, योग्यता और निष्पक्षता के सर्वोच्च मानकों का पालन करते हुए राज्य के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होता है।
3. जन-सामान्य में और अपने राज्य में अपनी ईमानदार, न्यायपूर्ण, तार्किक, साफ-सुथरी एवं निष्पक्ष मित्रतापूर्ण सरकारी सेवक की छवि को बनाए रखें।
4. मामलों को निपटाने में सदैव ईमानदार और निष्पक्ष भावना का प्रदर्शन करें। आपकी दृष्टि हमेशा न्यायसंगत होनी चाहिए।
5. जन-सामान्य, अधीनस्थ कर्मियों तथा सहकर्मियों के प्रति सामान्य शिष्टाचार बरतें।
6. श्रेष्ठ व्यवहार सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी है। आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें, जैसे व्यवहार की आप खुद के प्रति दूसरों से अपेक्षा रखते हैं।
7. अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करना न भूलें। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा ईश्वर की पूजा का सर्वश्रेष्ठ रूप है।
8. किसी भी समय अपने कर्तव्य की न उपेक्षा करें और न काम के प्रति समर्पण की भावना में कमी लाएँ। निर्णय संबंधी वास्तविक भूलों या त्रुटियों के अतिरिक्त यदि कोई कर्मचारी कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना में कमी या लापरवाही प्रदर्शित करता है तो उसके विरुद्ध आचरण नियमवाली/स्थायी आदेशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
9. अपने निर्णय, पक्षपात या अतार्किक भावना से न लें। आपके निर्णय हर दृष्टि से न्यायसंगत होने चाहिए।
10. फाइलों या मामलों को निपटाने समय व्यक्तिगत पसंद या नापसंद, पूर्वाग्रह आदि से प्रभावित न हों।

कन्या केलवणी योजना

महिला साक्षरता व शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए 'कन्या केलवणी योजना' (कन्या शिक्षा अभियान) महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। यही कारण है कि भारत में महिला साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। महिला साक्षरता 12 फीसद की दर से बढ़ रही है। फिलहाल देश में साक्षरता की दर 74 फीसद तक पहुँच गई है। गुजरात में साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 79.31 फीसद है और इसमें महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो यह 70.73 फीसद है।

इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि पिछले कुछ दशकों से ज्यों-ज्यों महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है, भारत विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इसने न केवल मानव संसाधन के मौके बढ़े हैं, बल्कि कामकाज और वातावरण में भी बदलाव आया है। महिलाओं के शिक्षित होने से न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास में भी तेजी आई है।

महिला साक्षरता में एक बात और सामने आई कि इससे शिशु मृत्युदर में गिरावट आ रही है और जनसंख्या नियंत्रण को भी बढ़ावा मिल रहा है। हालाँकि उसमें और प्रगति की गुंजाइश है। स्त्री-पुरुष समानता के लिए जागरूकता जरूरी है।

नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कई नीतियाँ तैयार कीं। गुजरात में साक्षरता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है।

बालभोग योजना

निर्धन छात्रों को विद्यालय में दोपहर का भोजन मुहैया कराने के लिए 'बाल भोग योजना' शुरू की गई। इस योजनांतर्गत विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में बच्चों को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। इससे न केवल छात्रों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, बल्कि वे मन लगाकर शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। इससे बीच में ही विद्यालय छोड़कर जाने की स्थिति भी सुधारी है।

केंद्र सरकार का निर्देश था कि बच्चों को मध्याह्न अवकाश में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मानकों में परिवर्तन करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में कम-से-कम 450 कै लोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध हो।

'बालभोग योजना कार्यक्रम' के मुख्य उद्देश्य के तहत नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षा की विभिन्न योजनाओं में अत्यधिक पूँजी निवेश कर रही है। इसका पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा, जब बच्चे कुपोषण से मुक्त होकर अपनी पूर्ण क्षमता से शिक्षा ग्रहण करते रहें। 'बालभोग योजना' इस लक्ष्य

को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कड़ी है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमिकरण के निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति होगी—

1. प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि होगी, ताकि कोई निरक्षर न रहे।
2. छात्रों को पूरे समय स्कूल में रोके रहना तथा विद्यालय छोड़ने की उनकी प्रवृत्ति में कमी।
3. निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता का विकास।
4. छात्रों को पौष्टिक आहार इस 'बालभोग योजना' का मुख्य उद्देश्य है।
5. विद्यालय में सभी जाति एवं धर्मों के छात्र-छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनमें सामाजिक सौहार्द, एकता और परस्पर भाई-चारे की भावना जगाना।

समग्र बाल विकास सेना योजना

गुजरात सरकार की 'समग्र बाल विकास सेवा योजना' (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत गुजरात में सन् 2001 में पहली बार समस्त बाल विकास योजनाओं को एक छत के नीचे लाया गया। वर्तमान में गुजरात में आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत 336 योजनाएँ, विभाग और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।

आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की एक झलक देखें—

1. राज्य में कुल 50,123 आँगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं।
2. 28,767 आँगनवाड़ी केंद्र सरकारी भवनों में हैं।
3. 93,290 महिलाएँ और युवतियाँ आँगनवाड़ी में सेवारत हैं।
4. 16,21,929 गर्भवती महिलाओं और युवतियों का मार्गदर्शन और पोषण सम आहार।
5. 28,57,296 लाभार्थी बच्चे।
6. दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक 'समग्र बाल विकास सेवा योजना' का लाभ पहुँचाने हेतु राज्य सरकार ने आँगनवाड़ी वैन की शुरुआत की।
7. देश में पहली बार गुजरात सरकार ने आँगनवाड़ी केंद्रों को दो गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन, गैस का चूल्हा और इडली बनाने की लिए कुकर की सुविधा प्रदान की।
8. प्रतिवर्ष 36 लाख बच्चों का आरोग्य परीक्षण किया जाता है।
9. 5,200 गरीब बच्चों को किडनी, कैसर और हृदय संबंधी रोगों से मुक्त करने के लिए उनकी निःशुल्क शल्य-चिकित्सा हुई।

गरीब को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था, हर जिले में गरीब कल्याण मेले का आयोजन। यह आयोजन वास्तव में दरिद्र नारायण की सेवा का महायज्ञ था। हर जिले में आयोजित गरीब कल्याण मेले में लाखों आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में रोजगार के साधन बढ़े। किसी को राशि का चेक मिला तो किसी को लॉरी तो महिलाओं को सिलाई मशीन मिली। किसी को ट्रैक्टर मिला तो, किसी को जमीन का प्लॉट मिला। पूरे गुजरात में 342 गरीब कल्याण मेले में लगभग 26 हजार करोड़ की राशि एवं रोजगार के साधन की सहायता दी गई। इसमें आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के लोग शामिल थे।

सरकारी योजनाओं का लाभ सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों की उपस्थिति में बाँटने का प्रयास शायद यह पहला प्रयोग होगा। इस गरीब कल्याण मेले में से गरीबी से लड़ने के लिए साधन मिल गए। गरीब कल्याण मेले में सहायता प्राप्त हर व्यक्ति को लगता था कि अब वह स्वाभिमान से जी सकेगा। अपना छोटा-मोटा व्यवसाय खुद कर सकेगा। पहले सरकारी कामकाज के जानकार बिचौलिए-दलाल गरीब को मूर्ख बनाकर सरकारी पैसे अपने घर ले जाते थे। मगर इस गरीब कल्याण मेले में मुख्यमंत्री, मंत्री खुद जाकर सार्वजनिक रूप से लोगों को सहायता राशि और सामग्री देते थे, इस कारण बिचौलिए का साम्राज्य खत्म हो गया। चपरासी से लेकर कलेक्टर आदि सभी इस गरीब कल्याण मेले की सफलता के लिए, और गरीब को सहायता मिले इस हेतु गाँव-गाँव में घूमे। पता लगाया कि कहाँ इन योजनाओं की आवश्यकता है। इस गरीब कल्याण मेले से किसी गाँव में 30 लोगों को लाभ मिला है तो किसी गाँव में 50 या 60 लोगों को लाभ मिला। इसमें नाई से लेकर मोची और दरजी से लेकर छोटी सी लॉरी तक शामिल है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, “मेरी सरकार गरीबों के लिए ही काम करती है। गाँव में रहनेवाला मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता स्वाभिमान से जीवन जी सकें, इस हेतु गरीब कल्याण मेलों का आयोजन हुआ है।” गरीब कल्याण मेलों का एक अच्छा पहलू भी सामने आया। नरेंद्र मोदी ने अपना अनुभव बताया। वे कहते हैं, “एक गरीब नाई को गरीब कल्याण मेले में उसके उपयोग साधन दिए तो उसने उसका ठीक ढंग से उपयोग कर हिम्मतनगर में दुकान खोली। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। वह मुझसे मिलने मोड़सा आया और कन्या शिक्षा हेतु 251 रुपए दिए तथा गरीब कल्याण मेले का आभार माना, क्योंकि इसके कारण उसकी अच्छी आय शुरू हो गई।”

नरेंद्र मोदी मानते हैं कि मैं ही नहीं, सभी लोग (विरोधी भी) जानते हैं कि गरीब कल्याण मेले गरीबों की शक्ति हैं, उनकी आस्था हैं। गरीब कल्याण मेला गरीबों के जीवन में चेतना-स्वाभिमान लाने का एक सार्थक प्रयास है। गरीब कल्याण मेले के आयोजन से गरीब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

पंचामृत संकल्पना का यज्ञ

अक्टूबर 2001 और वर्ष 2014 के गुजरात में जो फर्क नजर आता है, वह है जमीन-आसमान जैसा। पिछले एक दशक के मोदी के कार्यकाल के दौरान प्रदेश का समूचा परिवेश ही बदला नजर आता है। अक्टूबर 2001 में किसी ने कल्पना भी न की होगी कि मोदी के एक दशक के कार्यकाल में गुजरात अपनी विशिष्ट अस्मिता और गरिमा के साथ विकास के विशिष्ट स्पर्श के साथ समग्र देश का अव्वल राज्य कहलाएगा? यह कल्पना तब अस्वाभाविक भी थी। यह समय था, जब गुजरात अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। विकास के अनेक आयाम स्थापित किए जाने के बाद भी भविष्य के समृद्ध गुजरात की कल्पना इसलिए नहीं हो सकती थी, क्योंकि तब विकास की प्रक्रिया को गतिशीलता देनेवाले आदर्श, दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व का अभाव था। स्थूल अर्थ में राज्य का विकास एक अलग बात है और मात्र राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अपितु विश्व स्तर पर जिसे गंभीरता से लेना पड़े, उसे विशिष्ट गौरव के साथ समग्र देश में अपना स्थान स्थापित करना दूसरी बात है। हाँ, गुजरात ने पिछले 12 वर्षों में समग्र देश में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित कर लिया है।

भाजपा की चुनौतियाँ

याद आते हैं अक्टूबर 2001 के वे दिन। कितने मुश्किल दिन थे। गुजरात में विकास की प्रक्रिया को आगे ले जाने के संदर्भ में...! शासक पक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लग चुका था, दूसरी तरफ इस अनिश्चितता और अस्थिरता के कारण राज्य के प्रशासन पर पड़े नकारात्मक प्रभावों से गुजरात को बाहर लाने की चुनौती सामने थी। यह समय था, जब 1999-2000 और 2001 के अकाल के संकटपूर्ण दिनों की मार से गुजरात का सामाजिक जीवन उबरा नहीं था। लगातार तीन साल अकाल या अर्द्ध-अकाल के कारण गुजरात की अर्थव्यवस्था की नींव हिलने लगी थी। राज्य के सर्वांगीण विकास की आधारशिला, राज्य की समृद्ध अर्थव्यवस्था ही बन सकती है। अर्थव्यवस्था की स्थिति जब डौँवाँडोल हो, तो राज्य के सर्वांगीण विकास की कल्पना कैसे हो सकती है? इसके बावजूद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले बारह वर्षों के शासन में गुजरात ने तमाम क्षेत्रों में विकास के सर्वोच्च शिखर हासिल किए हैं।

प्रारंभिक वर्षों में लोक कल्याण मेलों के आयोजन के साथ गुजरात ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की ओर यात्रा शुरू की। लोक कल्याण मेलों से लोगों में विश्वास की भावना पैदा हुई। ऐसे ही एक मेले को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, “सरकार कोई उपकार नहीं कर रही। आम गरीब व दुःखी मानव तथा दबे-कुचले वर्गों में आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास जागे, इस प्रकार की सेवा-भावना से सेवा कर रहे एक सेवक की तरह सरकार की भूमिका रहेगी। गरीब मानव का हाथ पकड़कर उसे आत्मनिर्भर बनाएँगे, तभी समाज की शक्ति जागेगी। इसके लिए हमें ज्ञानशक्ति, जलशक्ति, ऊर्जाशक्ति, जनशक्ति और रक्षाशक्ति इन पाँचों का समन्वय कर अमृत का निर्माण करना है। जो समाज इस पंचामृत का पान करेगा, उस समाज का विकास चिरंजीवी होगा।”

पिछले बारह वर्षों के उनके कार्यकाल में गुजरात ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उसका सारांश देखें, तो प्रशासन में गतिशीलता मात्र अधिकारी या कर्मचारी नहीं, बल्कि एक कर्मयोगी बनकर प्रजानिष्ठ दृष्टिकोण का प्रशासन में आविष्कार हुआ है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासन को गतिशील बनाने के जो प्रयास किए, वे यदि नहीं किए जाते, तो आज प्रशासन की स्थिति कुछ और ही होती।

विकास की धारा

वर्ष 2001-02 में कृषि, सिंचाई, जलापूर्ति, ऊर्जा, शिक्षा, सड़क एवं परिवहन, स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत तथा ग्रामीण विकास, मत्स्योद्योग, वन, समाज कल्याण आदि विभागों की उपलब्धियों की तुलना छह साल बाद यदि आज की जाए, तो इन विभागों की अलग-अलग योजनाओं से पूर्व के चालीस वर्षों के कार्यकाल में कुछ भी उपलब्धियाँ हासिल नहीं की जा सकीं। यशस्वी उपलब्धियाँ मात्र बारह वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हासिल की हैं। कृषि विभाग में कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि आज अपनी चरम सीमा पर है। शिक्षा अनुसंधान तथा वितरण के बुनियादी कामकाज से आज राज्य की कृषि विकास दर 10 प्रतिशत पहुँची है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। एक समय औसत वार्षिक कृषि मूल्य उपार्जन 9000 करोड़ रुपए था, वह एक लाख करोड़ पर पहुँचा है। सिंचाई व जलापूर्ति क्षेत्र में जल संचय एवं नर्मदा योजना आधारित पाइप लाइन योजना से राज्य के नौ हजार से ज्यादा गाँवों में नर्मदा का पानी पीने के लिए पहुँचने लगा है। ऊर्जा विभाग की बात करें, तो समग्र देश में किसी राज्य ने कल्पना भी नहीं की, वैसी लगातार 24 घंटे श्री फेज से बिजली से राज्य के तमाम गाँवों को चकाचौंध करनेवाली ज्योतिग्राम योजना से ऊर्जा विभाग ने अभूतपूर्व उपलब्धि का नया अध्याय रचा है। इसी प्रकार राजस्व विभाग में ई-धरा किसानों को छूने वाले राजस्व कानूनों में सुधार, पंचायत विभाग में ग्रामीण सचिवालय की कल्पना से लेकर ई-ग्राम, विश्वग्राम जैसी योजना, वन विभाग में वनबंधु योजना, मत्स्योद्योग विभाग में सागरखेड़ योजना, स्वास्थ्य विभाग में कन्या भ्रूण हत्या निरोध हेतु प्रबल अभियान, शिक्षा विभाग में कन्या शिक्षा अभियान, सड़क एवं भवन विभाग में प्रगति-पथ का एक उम्दा कॉन्सेप्ट, ऐसी कई योजनाएँ संबद्ध विभाग ने लागू कीं और उसके फलस्वरूप आज गुजरात विकास की चरम सीमा पर है।

यह विकास संभव कैसे हुआ? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 40 वर्ष के विकास की प्रक्रिया का निरीक्षण किया, फिर उसका गहन चिंतन किया। इस समयावधि के दौरान राज्य के भौतिक विकास के मार्ग में आई बाधाएँ, विकास की चुनौतियाँ, विकास के लिए किए गए आयोजन

तथा उसके क्रियान्वयन के परिणामों का अध्ययन किया गया। जिस सरकारी प्रशासन से विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसकी कार्यशैली का उन्होंने अभ्यास किया और उसके बाद राज्य के विकास की विशिष्टता, आपत्तियों के बीच निरंतरतापूर्ण विकास किस तरह हो सके, उसकी रणनीति, सरकारें बदलने के बावजूद नीतियों में निरंतरता, परिवर्तन को प्राप्त होने वाले परिप्रेक्ष्यों के साथ विकासोन्मुख प्रशासन की जरूरत आदि बातों का विचार हुआ और खींचे गए कल्पना चित्र के मुताबिक वर्तमान गुजरात का स्वरूप उभरा।

पंचामृत से हुई सरकार चिरंजीवी

राज्य के विकास की आधारशिला अंततः राज्य के मूलभूत संसाधन, उसकी वैचारिक प्रवाहिता, जल संसाधन, ऊर्जा के अलावा संरक्षण पर निर्भर रहती है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास के लिए जो कुछ बुनियादी चिंतन किया, उसका निष्कर्ष यह निकला कि इस राज्य की धरोहर समान पाँच शक्तियों का समन्वय होना चाहिए, जो राज्य की विकास प्रक्रिया में अमृत सिंचन का काम कर सके। कौन सी थीं ये पाँच शक्तियाँ? ज्ञानशक्ति, जलशक्ति, जनशक्ति, ऊर्जाशक्ति और रक्षाशक्ति। इन पाँचों शक्तियों के समन्वय के फलस्वरूप या शक्तियों को घोंट-घोंटकर जो अमृतरस निकला, उससे बनता है 'पंचामृत'। जो समाज इस पंचामृत का पान करता है, उस समाज का विकास चिरंजीवी हुए बिना नहीं रहता।

ज्ञानशक्ति

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों में पाँच शक्तियों के विकास कार्यों को विकास के साथ राज्य की जनता को पंचामृत जैसा पान कराया है। इसके चलते राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में विकास या परिवर्तन की चमत्कारिक लहर का व्यापक अनुभव हो रहा है। इसे समझने के लिए राज्य के विकास की आधारशिला साबित हुई। इन पाँच शक्तियों अर्थात् पंचामृत के विचार को विस्तार से समझना जरूरी है। राज्य सरकार ने प्रथम ज्ञानशक्ति को अग्रसर किया। राज्य की बौद्धिक संपदा को महत्त्व देकर उसके जरिए राज्य का विकास पर चिंतन-मनन का आयोजन किया। इस आयोजन के तहत ढाँचागत शिक्षा सुविधा, गुजरात ग्लोबल एजुकेशन ऐंड एंज्लॉयमेंट बोर्ड, ज्ञानरथ प्रोजेक्ट, दूरतर शिक्षा, विद्यालक्ष्मी योजना के जरिए कन्या शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान द्वारा मानव संसाधन का उपयोग कर रोजगार के अवसर पैदा करने जैसी बातें शामिल की गई।

जहाँ तक राज्य में शिक्षा क्षेत्र का संबंध है, तो यह वास्तविकता माननी पड़ेगी कि राज्य में कन्या शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है। इसमें गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से कन्या शिक्षा, शाला प्रवेशोत्सव से जो अभियान शुरू किया गया, उसके फलस्वरूप कन्या शिक्षा की साक्षरता दर में वृद्धि हुई, वहीं एक से पाँचवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या भी घटी। इस अभियान के तहत स्कूल शुरू होने के प्रारंभिक दिनों में ही राज्य के जिलों में कम कन्या साक्षरता वाली तहसीलों के सुदूरवर्ती गाँवों में कन्या शिक्षा रथ के जरिए कन्या शिक्षा का एक बड़ा अभियान गुजरात की जनता ने देखा। इतना ही नहीं, इसके अच्छे नतीजे भी अनुभव किए। राज्य में औसत बच्चे को भी प्राथमिक शिक्षा लेने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन केवल संवैधानिक अधिकार से बच्चा प्राथमिक शिक्षा पाने लगेगा, यह सोचना भ्रम है। इसीलिए विद्यालय प्रवेशोत्सव अभियान से गाँव-गाँव में बच्चों का विद्यालय प्रवेशोत्सव हर्ष और उल्लास का माध्यम बना। इस प्रकार के कार्यक्रमों में अभूतपूर्व जन भागीदारी देखने को मिली।

ज्ञानशक्ति के आविर्भाव के लिए पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाली प्रत्येक कन्या को 1000 रुपए का बॉण्ड, सातवीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करनेवाली हर लड़की को इस बॉण्ड की रकम ब्याज सहित मिलती है। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों की कन्याओं को स्कूल में दाखिले के बाद से 60 किलो अनाज मुफ्त देना, रोजी-रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाले परिवारों के बच्चों को अस्थायी निवास के दौरान स्थानीय स्कूल में प्रवेश आदि को शामिल कर इस अभियान को जीवंत बनाया गया।

ज्ञानशक्ति के अन्य उल्लेखनीय पहलुओं में शिक्षा शुद्धीकरण अभियान, कर्मयोगी योजना द्वारा शिक्षकों को सघन प्रशिक्षण जैसी बातों को जोड़ा गया है। शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम समझ बैठे और शिक्षा को मंडी समझकर व्यापार करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके शिक्षा शुद्धीकरण द्वारा सरस्वती साधना के माध्यम को अधिक सक्षम बनाया गया। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों की निदान कसौटियाँ आयोजित की गई। जो बच्चे गणित, विज्ञान जैसे विषयों में कमजोर पाए गए, उन्हें खास प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार राज्य की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का सफल प्रयास हुआ। उच्च शिक्षा में और राज्य से बाहर के पाठ्यक्रमों में गुजरात के युवा पीछे न रह जाएँ, इसके लिए गणित-विज्ञान जैसे विषय अंग्रेजी भाषा में शामिल किए गए।

प्राथमिक स्कूल के बच्चे से लेकर उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों तक को दुर्घटना समूह बीमा योजना में शामिल कर विद्यार्थियों को सुरक्षा छत्र देने का एकमात्र श्रेय गुजरात को जाता है।

आदिवासी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की व्यापकता बढ़ाने के लिए चार नए बी.एड. कॉलेज शुरू करने के साथ राज्य भर में 71 पीटीसी कॉलेज और 603 माध्यमिक स्कूल शुरू कर प्रत्येक शिक्षक को वर्ग और प्रत्येक वर्ग को शिक्षक का सपना गुजरात ने साकार किया।

कच्छ यूनिवर्सिटी की स्थापना के अलावा तकनीकी-व्यावसायिक और कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिक के उच्च अभ्यास के लिए निरमा इंस्टीट्यूट तथा धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ज्ञानशक्ति की इस ज्योति से गुजरात को अग्रिम पंक्ति में ले जाने का प्रकाश-मार्ग प्रशस्त हुआ।

जलशक्ति

ज्ञानशक्ति के साथ ही जलशक्ति के आह्वान के साथ राज्य सरकार ने सरदार सरोवर के साथ जल संचय की विभिन्न योजनाओं से राज्य की सूखी धरती को सुजला-सुफलाम् बनाने का जो सपना सँजोया, उसके फल आज गुजरात को मिलने लगे हैं। एक समय राज्य में ऐसा भी था कि एक घड़ा पानी के लिए महिलाओं-बेटियों के मीलों दूर जाना पड़ता था। लगभग वर्ष-दर-वर्ष अकाल तथा उसके कारण राज्य के छोटे-मध्यम स्तर के जलाशय लगभग खाली रहते, दूसरी तरफ कुएँ और बोरवेल भी रिक्त हो जाते। आज से पचास साल पहले राज्य का जो किसान भूमिगत जल से खेती करता था, वह 15-200 फीट से लेकर 1500 से 2000 फीट गहराई से पानी खींचकर खेती करने को विवश हो गया, क्योंकि धरती की जलराशि का वर्ष दर वर्ष खूब दोहन हो रहा था। नरेंद्र मोदी ने जलशक्ति की महत्ता को समझकर जल संचय के विचार को अधिक स्वीकृत बनाया और इसके फलस्वरूप आज राज्य में 85000 से अधिक तटबंध, पौने दो लाख से ज्यादा कृषि तालाब, हजारों बोरी बाँध के अलावा हजारों गाँव तालाब, सीमा तालाब, नए जल मंदिर (पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करने का अभियान), सुजला-सुफलाम् स्प्रेडिंग कैनाल जैसी अनेक छोटी-बड़ी योजनाओं के कारण पिछले पाँच वर्षों में करोड़ों घन मीटर बारिश का पानी जमा हो सका, इसका परिणाम चमत्कारिक मिला। सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात तथा पूर्वी गुजरात के अनेक इलाकों में जहाँ जल संचय के काम हुए, इन इलाकों में वर्षों तक सूखे रहे बोरवेल-कुएँ अब पिछले तीन वर्षों से पानी से छलक रहे हैं। जिन कुओं में रस्सी छोटी पड़ जाती थी, वहाँ आज हाथ बढ़ाकर अंजलि भरकर पानी पिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ जो बोरवेल वर्षों से सूखे पड़े थे, वे अब वर्षा ऋतु में जल से छलकते रहते हैं। ये नजारे अब आम हैं। जल संसाधन के ऐसे सुंदर प्रसंग राज्य की जनता ने पिछले वर्षों में कभी कल्पना में भी नहीं सोचे थे।

जल संचय के साथ जल प्रबंधन की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ड्रिप स्प्रिंकलर इरीगेशन का कार्यक्रम लागू किया गया। 1500 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ राज्य में ड्रिप इरीगेशन योजना लागू की गई और इससे 4.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरीगेशन हुआ है। जल प्रबंधन जल संसाधन का एक मुख्य आधार साबित हुआ। पिछले चार वर्षों में बहुत ही अच्छी बरसात के हालात बने और इसके साथ ही बरसाती जल संग्रह का अधिकतम आयोजन होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नया बल मिला है, जिसका श्रेय जलशक्ति को ही जाता है।

ऊर्जाशक्ति

उद्योगों के विकास की नींव में है ऊर्जाशक्ति। ऊर्जा औद्योगिक विकास का मुख्य परिचालक है। उद्योगों को सस्ती और समय पर बिजली देने की दिशा में कदम उठाने की पहल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जाशक्ति के आह्वान के साथ की। गुजरात में बिजली उत्पादन तथा बिजली वितरण क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के परिणाम दिखने लगे हैं।

गुजरात में गैस का जो उत्पादन हुआ है, उसे बिजली क्षेत्र में उपयोगी बनाने की ठोस व्यवस्था की गई। इस कारण राज्य ने ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। उद्यमियों के लिए बिजली के मामले में कम-से-कम तकलीफदेह स्थिति का निर्माण हुआ। सरदार सरोवर बाँध की बात करें, तो बाँध की ऊँचाई 121 मीटर तक पहुँचने से जल ही नहीं, बिजली का भी प्रपात बहने लगा। इसके अलावा पवन चक्की द्वारा ऊर्जा प्राप्ति की दिशा में भी निश्चित कदम उठाए गए। कल्पसर योजना के तहत समुद्री लहरों के जरिए पाँच हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का वर्तमान सरकार ने जो संकल्प लिया, उस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है।

औद्योगिक विकास में समग्र देश में द्वितीय स्थान पर रहे गुजरात ने प्रथम स्थान पर पहुँचने के लिए औद्योगिक विकास की व्यापक नीति अपनाई। ढाँचागत सुविधाओं के व्यापक नेटवर्क के विकास के साथ-साथ ऊर्जाशक्ति के तमाम स्रोतों की संभावनाओं के समन्वय के आधार पर बिजली उत्पादन की व्यवस्था की गई। कोयला आधारित बिजली केंद्रों के प्लांट लोड फैक्टर बढ़ने के लिए पावर स्टेशनों के सुधार के अलावा गुजरात में अब प्राकृतिक गैस आधारित बिजली उत्पादन व समुद्र तटों पर पवन ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने की व्यवस्था की गई।

पवन ऊर्जा तथा समुद्री ज्वार की लहरों से बिजली पैदा करने की प्रोत्साहक नीतियाँ भी बनीं। 1500 करोड़ का गैस ग्रिड प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए, जिसमें पाँच जोन बनाकर घरलू गैस तथा औद्योगिक गैस पाइप लाइन से वितरित करने का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों में गैस तथा खनिज तेल के उत्पादन के अलावा एलएनजी, सीएनजी ईंधन के लिए जो प्रोजेक्ट लागू किए गए, उसके कारण राज्य के पर्यावरण में गुणात्मक परिवर्तन आया है।

राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने जो व्यवस्था की और जो कठोर कदम उठाए, उसके कारण बिजली चोरी की घटनाएँ अब समाप्त सी हैं। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में बिजली चोरी प्रतिरोधक कानून पारित कर उसके सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी भी ली गई। इसके परिणामस्वरूप बिजली की चोरी करनेवालों को तीन साल की कड़ी सजा और दो लाख रुपये के जुर्माने की सख्त कानूनी सजा का प्रावधान हुआ और अपेक्षित नतीजे मिले। इस प्रकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में बिजली चोरी में कमी आई और ऊर्जाशक्ति की महत्ता स्थापित हुई।

रक्षाशक्ति

पाँच शक्तियों में महत्वपूर्ण शक्ति यानी रक्षाशक्ति। जो समाज सुरक्षा की अनुभूति न करे, वहाँ विकास की प्रक्रिया कैसे बनी रह सकती है?

विकास अभी संभव होता है, जब राज्य में शांति और विश्वास का माहौल हो। वैसे तो गुजरात की छवि एक शांतिप्रिय राज्य की ही है, इसके बावजूद पूर्व के वर्षों में राज्य की शांति भंग करने के कोई कम प्रयास नहीं हुए। खासकर पड़ोसी राष्ट्रों की ओर से आतंकवाद का भय गुजरात ने वर्ष 2001-02 में अनुभव किया है। दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति द्वारा आतंकवाद को दबाया नहीं जाता तो आज गुजरात भी आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया होता, लेकिन रक्षाशक्ति के सहयोग से गुजरात ने मात्र आतंकवाद को नहीं दबाया, बल्कि आज विश्व के उद्योगपतियों की नजर राज्य की शांति के कारण गुजरात पर टिकी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वाइब्रेंट गुजरात के तहत करोड़ों रुपये के मूल्यवान् पूँजीनिवेश हुए और आज उसके कारण करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट राज्य में डाले जा चुके हैं। इस देश के प्रथम पंक्ति के उद्योगपति भी नए उद्योगों की स्थापना के लिए गुजरात पर निगाहें जमाए हैं। यह सब रक्षाशक्ति के फलस्वरूप ही साकार हो सका।

रक्षाशक्ति के तहत जो कुछ कार्य हुआ, उसके तहत संगठित अपराध नियंत्रण के लिए गुजकोक कानून का विधेयक पारित कर उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल महोदय को भेजा गया। ब्राउनसुगर सहित मादक पदार्थों का करोड़ों का कीमती भंडार जब्त हुआ। गोधरा हत्याकांड के समाज विरोधी तत्त्वों के खिलाफ पोटा, सहकारिता बैंकिंग में निहित स्वार्थी तत्त्वों के आर्थिक अपराध और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए बिना किसी भेदभाव के दोषियों पर भारी जुर्माना लगाया और जेल की सजा कराई गई, आतंकवाद का सामना करने के लिए चेतक कमांडो का गठन, प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थानों का निर्णय, सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने व सीमा पार देश विरोधी गतिविधियों के प्रभावी प्रतिकार के लिए सीमावर्ती गाँव का शक्ति ग्राम के रूप में विकास, नाकॉटिक्स की अवैध हेराफेरी रोकने के लिए नए कानून सहित अनेक कदम उठाए गए। गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी 'गुजकोक' द्वारा संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम, गुजरात प्रोटेक्शन ऑफ इंटरैस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स ऐक्ट द्वारा नॉन बैंकिंग संगठनों में उपभोक्ता सुरक्षा, सहकारी बैंकों के प्रबंधन में गुणात्मक सुधार के लिए अध्यादेश, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था, कच्छ-जामनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बार दौरे कर सुरक्षाकर्मियों को प्रोत्साहन, सैन्य अधिकारियों के बीच नियमित व परिणामदायी आदान-प्रदान, सेना, नौसेना, वायुसेना के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ नियमित चर्चा, कोस्ट गार्ड के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग, जखौ में कोस्ट गार्ड स्टेशन की स्थापना, तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए स्पीड बोट के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख, आतंकियों के खिलाफ काल के समान कानून पोटा का समर्थन सहित अनेक कदम उठाए गए हैं।

जनशक्ति

मानव संसाधन का उचित उपयोग ही वर्तमान को अधिक प्रगतिशील और कार्यक्षम बनाता है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव विकास के इस पहलू को महत्त्व देकर अनेक सिद्धियाँ हासिल की हैं। पिछले पाँच वर्षों में तटबंधों की संख्या 85 हजार तक पहुँची। इसकी सफलता में जनभागीदारी तथा मानव संसाधन का उचित उपयोग है। राज्य भूकंप की पीड़ा से उबर सका। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह जनशक्ति ही थी। गुजरात की स्थापना के बाद पहली बार लोकतंत्र की गरिमा ने ऐतिहासिक माइल स्टोन अंकित किया है। राज्य में पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं और विधानसभा-सांसदों के तमाम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। गुजरात को अशांत मानने वाले विरोधियों के मुँह शांत जनमत की इस विराट् क्रांति से सिल गए।

गुजरात भर में जनशक्ति की लहर फैल गई। ग्रामसभा में अकूत क्षमता है, जहाँ गाँव के लोग खुद ही विकास पर मंथन करें और निर्णायक बन सकते हैं। यह बात अब सरकारी प्रशासन भी मानने लगा, फलस्वरूप ग्रामीण विकास के लिए आलस्य झाड़ कर प्रशासन भी गतिशील बना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठकर गाँव के लोगों के साथ संवाद करते हैं, तब उसमें आई जागरूकता तथा विकास की इच्छा के उन्हें दर्शन होते हैं।

गाँव की जनता चुनावी रंजिश-वैमनस्य और विवाद से छुटकारा पाने को आतुर है। समरस गाँव योजना को गाँव की जागरूक जनता और पंचायतों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिला है। राज्य की पाँच हजार से अधिक ग्राम पंचायतें समरस बन चुकी हैं। निर्विरोध चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों में स्पर्धा जागना क्या शुभ संकेत नहीं है? पूरा गाँव चुनाव के सुख-दुःख, नाराजगी-खुशी छोड़कर एकजुट होकर विकास के निर्णय ले, तो ग्राम स्वराज्य की सच्ची दिशा में प्रयाण ही है न।

यह सरकार गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ढाँचागत सुविधाएँ ही नहीं, अपितु गाँवों में सुख-शांति, गाँवों की आत्मनिर्भरता, गाँवों को विश्व के साथ जोड़कर विश्वग्राम बनाने वाली कल्पना के साथ ग्रामसभा की प्रक्रिया को चेतनाशील बनाया और राज्य में 18 हजार से अधिक गाँवों में ग्राम सभाएँ आयोजित हुईं। 'वेस्ट से बेस्ट' की तर्ज पर गोबर को ऊर्जा के स्रोत में बदलने का नया दृष्टिकोण पेश किया गया, जिसमें प्राकृतिक खाद, गोबर-गैस और बिजली के उत्पादन की प्रक्रिया बनाकर गाँव को ऊर्जा ग्राम बनाने का विचार है। ग्रामीण सड़कों के शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने में गुजरात देश का पहला राज्य बना, तो पहली बार समर्थन मूल्य पर खरीद की पहल राज्य सरकार ने करके कृषकों को सहारा दिया। बाजरा, मूँगफली और मक्का की खरीद की सरकार ने!

इस प्रकार पिछले बारह वर्षों में राज्य के विकास के लिए पाँच शक्तियों के अमृत का जो सिंचन हुआ, उसके फलस्वरूप विकास के बीजांकुर फूटे, कलियाँ भी फूटी हैं। आगामी दिवसों में विकास का वटवृक्ष बनकर उभरने के आसार हैं। इसीलिए 2001 के गुजरात की तुलना में 2014 का गुजरात अपनी विशिष्ट गरिमा के साथ स्थापित हुआ है। गुजरात ने प्रगति के पंचामृत का रसास्वादन किया है। संवेदनशील नेतृत्व तथा प्रगति का यह पंचामृत समग्र भारत में गुजरात को अद्वितीय स्थान दिलाता है, साथ ही विकास व राजनीतिक इतिहास के पन्नों पर एक विशिष्ट

छाप भी छोड़ता है। गुजरात की कीर्ति-पताका दुनिया में लहराए, अब वह दिन दूर नहीं!

□□□